RE. SHORTAGE OF COAL IN POWER PLANTS IN U.P.

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के तीन-तीन थर्मल प्लांट्स में कोयला बिल्कुल खत्म हो गया है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में आ जाएगा। ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने नोटिस दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नोटिस का मैटर जीरो ऑवर में उठेगा। ...(**व्यवधान**)... आज जीरो ऑवर नहीं है, इसे हम कल देखेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : केन्द्र सरकार का यह जो उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है, इसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबने जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आज जीरो ऑवर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : सर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट कर दें कि वहां कोल की सप्लाई जारी रहे।

श्री उपसभापति : आपने आज नोटिस दिया है, इसे कल जीरो ऑवर में देखेंगे। ...(**व्यवधान**)... अब आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... श्री जुगुल किशोर।

THE BUDGET (GENERAL), 2014-15
AND
THE APPROPRIATION (NO.2) BILL, 2014
THE APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2014 – *Contd.*

श्री जुगुल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे देश के आम बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी नेता बहन कु. मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। मोदी सरकार का यह प्रथम बजट देश के वित्त मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया। मुझे इस पूरे बजट को पढ़ने का मौका मिला। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Sir, I am on a point of order. .... *(Interruptions)*... I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... There is no Cabinet Minister. ...*(Interruptions)*...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : आनन्द शर्मा जी, मुझे यहां इतना समय हो गया, फिर आप मेरे साथ अन्याय क्यों करते हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा : नहीं जानते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anand Sharma, do not try to demote him. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा : इनका परिचय देते ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, we are discussing Budget. ...*(Interruptions)*... But, there is nobody from the Finance Ministry. ...*(Interruptions)*... It is a very important financial Bill and there is nobody from the Finance Ministry. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : बैठो-बैठो, अभी आ जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI JAIRAM RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, you adjourn the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a collective responsibility. ...*(Interruptions)*... One Cabinet Minister is enough. ...*(Interruptions)*... Of course, I do agree that there should have been somebody from the Finance Ministry. ...*(Interruptions)*... But, there is one Cabinet Minister and we can proceed. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you adjourn the House. ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : बजट पर चर्चा हो रही है, फाइनेंस से कोई नहीं है। ...(**व्यवधान**)... अच्छे दिन आ गए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She was here. She had gone out just for two minutes, बैठिए-बैठिए ...*(Interruptions)*... One Cabinet Minister is also here. ...*(Interruptions)*... Everything is in order. ...*(Interruptions)*...

श्री जुगुल किशोर : महोदय, मैंने महसूस किया कि इस बजट पर पूरा खाका यू.पी.ए. सरकार का ही खाका है, केवल कुछ आंशिक परिंवतन एव कुछ नई बातों को जोड़ने के अलावा देश के बदलाव के बड़े मुद्दों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान देश के लोगों में नई आशाएं और नई उम्मीदें जगाई थीं, अच्छे दिन आने का आभास कराया था, बजट में वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। हमारे देश की यह सरकार महंगाई कम करने, भ्रष्टाचार मिटाने एवं विदेशों से भारत का काला धन वापस लाने तथा विकास का इतिहास बनाने का नारा देकर सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इस सरकार के दो महीने के कार्यों से तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उलटा-पुलटा हो गया है। महंगाई घटने के बजाए बढ़ गई, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ, रेल किराया अथवा आवश्यक वस्तुओं का मामला हो, मोदी जी के.पी.एम. बनने के बाद सभी चीजें महंगी हो गई हैं। आज भारत के बाजार में टमाटर सौ रुपए किलो से भी अधिक महंगा बिक रहा है। केवल सब्जी की ही बात नहीं, बल्कि ईंट, सरिया, सीमेंट और यातायात के सभी साधन महंगे हो गए हैं। महोदय, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में साढ़े 14 परसेंट यात्रा किराए में और साढ़े 6 परसेंट माल भाड़े में वृद्धि कर के सरकार ने देश के लोगों को कौन से अच्छे दिन दिखाए हैं? साथ ही देश की सरकार ने इस आम बजट में

भी लोगों को निराश ही किया है। अगर हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के संबंध में बजट में रखे गए प्रावधन की बात करें, तो वह भी निराशाजनक है क्योंकि भारत के अंदर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 23 परसेंट है और इस वर्ग के लिए बजटीय प्रावधान केवल 50,548 करोड़ का ही किया गया है जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के आधार पर बजट का 23 परसेंट यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए था। अगर ऐसा होता, तो शायद सारे देश के दलित यह महसूस करते कि श्री मोदी जी की सरकार ने यू.पी.ए. की सरकार से आगे बढ़कर कुछ काम किया है।

उपसभापति महोदय, हमारे देश में वर्ष 2010 में राष्ट्र मंडल खेलों का आयोजन हुआ। उन खेलों में दिल्ली प्रदेश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए रखी धनराशि, यानी स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के 744 करोड़ रुपए इन खेलों के आयोजन के लिए स्थानांतरित किए गए। कई बार हमारी पार्टी ने इसी सदन में यह मांग की है कि सरकार बताए कि दिल्ली के दलितों के विकास के लिए रखे गए 744 करोड़ रुपयों का स्टेटस क्या है? महोदय, आज तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वह मेरे भाषण में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें, तो कृपया इस बात को स्पष्ट करें।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि भारत के सभी प्रांतों में दलितों के विकास के लिए खर्च होने वाले स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की कितनी धनराशि केन्द्र सरकार अथवा योजना आयोग पर बाकी है? माननीय वित्त मंत्री जी कृपया इस बात को भी स्पष्ट करें। मुझे इस बात की जानकारी है कि जिस प्रकार दिल्ली प्रदेश में दलितों के विकास की धनराशि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए स्थानांतरित की गई थी, उसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

उपसभापति महोदय, बहुत दुख के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार के बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों को भरने एवं बैकलॉग को पूरा करने पर सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अकेले केन्द्रीय विभागों में ही इन वर्गों के 60 हजार से ज्यादा के पद रिक्त हैं, लेकिन इनकी भर्ती प्रक्रिया शून्य है। आज देश के अन्य प्रदेशों में न जाने कितना-कितना कोटा रिक्त पड़ा है। इस सरकार का भी ध्यान दलितों को रोजगार देने की तरफ बिल्कुल नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बी.पी.एल. की सूची, जो देश के गरीबों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बनायी जाती है, उसकी लंबे समय से समीक्षा नहीं हुई है। सच यह है कि आज भी करोड़ों गरीब देश में ऐसे हैं कि जो बी.पी.एल. की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इस सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। मैं सदन के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि बी.पी.एल. की सूची जो पहले बनी है, उसमें अनेकों नाम ऐसे हैं जो बी.पी.एल. की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन बी.पी.एल. कोटे का लाभ ले रहे हैं। क्या सरकार एक समय-सीमा निर्धारित कर बी.पी.एल. सूची की समीक्षा करा के वास्तविक गरीबों को बी.पी.एल. की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा करेगी?

[श्री जुगुल किशोर]

उपसभापति महोदय, अगर हम इस बजट में आवासीय व्यवस्था की बात करें, तो इस संबंध में सरकार ने कोई बड़ी योजना घोषित नहीं की है। देश के गरीब तो यह महसूस करते हैं कि आज जब एक चाय बेचने वाले और सियासत करने वाले नेता को देश का पी.एम. बनने का मौका मिला है, तो वे गरीबों को कम-से-कम आशियाना देने का काम तो करेंगे, लेकिन बजट में ऐसा नहीं हुआ है। इससे आवासहीन लोगों में बड़ी निराशा है। मैं यह कहता हूं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो देश के करोड़ों लोगों को कम-से-कम समय में आशियाना मिल सकता था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का शासन हमने देखा है। उन्होंने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लाखों गरीबों को मान्यवर काशीराम शहरी गरीब आवास योजना' के अंतर्गत दो कमरों के पक्के मकान बनवा कर, उनके रहने का ठिकाना देने में सफलता प्राप्त की। आप गुजरात का मॉडल तो देश में लाने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी की आवास योजना को देश में लागू क्यों नहीं करते? देश में 'इंदिरा आवास योजना' का संचालन हुआ था, लेकिन उन आवासों को बनाने के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है, वह इस महंगाई के दौर में काफी नहीं है। वैसे भी इस योजना का वास्तविक लाभ देश के गरीब लोग नहीं उठा सके, इसलिए इस योजना का विस्तार करके दो कमरों के पक्के मकान बनाकर देने का फैसला अगर सरकार कर ले, तो शायद देश के कुछ लोगों को राहत मिल सकती है।

महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय से विशेष पैकेज के तौर पर बहुजन समाज पार्टी 80 हजार करोड़ रुपए की मांग करती आई है। आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी इस मांग को उठाती रही हैं, लेकिन यू.पी.ए. की सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं चाहूंगा कि यह एन.डी.ए. की सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी की पुरानी मांग को स्वीकार करके जितना जल्दी हो सके 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज देने का निर्णय ले। वैसे भी उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं है। वहां विकास पूरी तरह से ठप हो गया है, रोजगार की कोई नीति सरकार लागू नहीं कर सकी, सूखे से किसान प्रभावित हैं, बढ़ते हुए अपराधों से तो पूरे प्रदेश की जनता भयभीत है। एन.डी.ए. सरकार को उत्तर प्रदेश की बदहाली और बढ़ते हुए अपराधों पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं देश के दलित छात्रों की एक बड़ी समस्या केन्द्र सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से दलित बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए जो धनराशि वजीफे के तौर पर दी जाती थी, वह आज बाधित है। हम चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर की बात करें, सभी प्रदेशों में दलित छात्रों को वजीफा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, न ही वे छात्र अपनी पढ़ाई आगे कर पा रहे हैं। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि देश भर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वजीफे की धनराशि महंगाई के हिसाब से शीघ्र दिलाना सुनिश्चित करे तथा इन वर्गों के छात्रों के लिए विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करे। भारतीय संविधान में केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था तो है, लेकिन आज देश यह महसूस करता है कि इन वर्गों के छात्रों के लिए निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि निजी शैक्षणिक निजी संस्थानों में पढ़ाई के

समान अवसर प्राप्त हो सकें। देश के बहुत दिनों से देश के दलितों ने इस मांग को उठाया हुआ है कि उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालय तथा सेना में भी आबादी के हिसाब आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहूंगा कि केवल न्यायपालिका और सेना में ही नहीं, बल्कि मीडिया के क्षेत्र में भी दलितों का आरक्षण होना चाहिए। केन्द्र सरकार के उच्च विभागों में भी विशेष तौर पर संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव जैसे पदों पर दलितों की भागीदारी शुरू हो। मैं चाहुंगा कि नई सरकार केन्द्र सरकार के विभागों में प्रमुख पदों पर भी दलितों को आरक्षण का अवसर प्रदान करे। आज पूरे देश के दलितों में इस बात को लेकर रोष होता है कि आजादी के 67 वर्षों के बाद भी उनके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा। आपने देखा कि हरियाणा में मिर्ची कांड, पंजाब में तलहन कांड, उत्तर प्रदेश में मोहनलाल गंज में गैंगरेप जैसी घटनाएं ऐसे नमूने हैं, जिनसे आज भी दिल दहल जाता है। सभी सरकारें दलितों के वोटों पर राज करती हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, बलात्कार, हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, तो सरकारें चुप बैठ जाती हैं। मैं देश के वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने बजट में व्यवस्था करें कि भारतवर्ष में दलितों के विरुद्ध जाति के आधार पर होने वाली हिंसक घटनाओं की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हों और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स केवल अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के साथ होने वाली घटनाओं की सुनवाई के लिए ही हों। आज हमें बहुत तकलीफ होती है, जब हमारे वाल्मीकि समाज के भाई-बहन अपने हाथों से सफाई, यहां तक कि मल-मूत्र उठाने का काम भी करते हैं, लेकिन उनको आज तक स्थायी कर्मचारी नहीं माना गया। आज भी उन्हें ठकेदारी प्रथा के आधार पर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है। लेकिन यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जब बजट पर बहस हो रही थी, तो सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद सफाई मजदूरों के विषय में बात कर रहे थे कि हमने उनके लिए इतनी व्यवस्था की, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश की आजादी के 67 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी स्थिति इस आजाद भारत में गुलामों जैसी बनी हुई है। उन्हें ठेकेदारी प्रथा में काम करने के लिए नौकरी पर रखा गया, लेकिन आज तक उन्हें रेग्युलराइज नहीं किया गया। इस दिल्ली प्रदेश में भी मैंने देखा कि वे 8,000 रुपए पर आज नौकरी करते हैं। क्या यह दयनीय दशा नहीं है? लेकिन केन्द्र सरकार के लोग फिर भी अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं रहते हैं और आंसू बहाते हैं कि वाल्मीकि समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात का एक इतिहास बनाया और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मियों को स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति करके उनके विकास के रास्ते को खोला। क्या देश की सरकार इस नीति का अनुसरण नहीं कर सकती? मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाए तथा उनको वे सब सुविधाएं मिलें, जो सुविधाएं किसी केन्द्र सरकार के कर्मचारी को मिलती हैं।

महोदय, हमारे देश की एक अजीब विडम्बना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के मूल भाव का ध्यान, जम्मू-कश्मीर में किसी भी प्रकार से नहीं रखा जा रहा है। पूरे देश में अनुसूचित जाति को आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अजीब बात है, जम्मू-कश्मीर के

[श्री जुगुल किशोर]

अनुसूचित जाति के गुर्जर, बकरवाल जाति के लोग अभी तक इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सके। तो क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में एस.टी. वर्ग को, एम.पी. या एम.एल.ए. के चुनाव में आरक्षण देने का निर्णय करेगी?

महोदय, आज पूरे भारतवर्ष में अगर किसी का बहुत बुरा हाल है, तो पिछड़े समाज के लोग, जिनकी आबादी आज 52 परसेंट से अधिक है, उनका है, लेकिन देश की सरकार का यह बजट इन 52 परसेंट के विकास के लिए मौन है। क्या कुसूर है इनका? जब काका कालेलकर आयोग एवं वी.पी. मंडल आयोग ने अपनी अनुशंसा में यह स्पष्ट कर दिया कि देश के इस पिछड़े वर्ग के हालात बहुत बदतर हैं, तो क्या सरकार को इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? न तो इन वर्गों के लोग राजनीति में हैं, न बड़ी सर्विसेज में हैं और न ही उद्योगों में हैं। इन पिछड़े वर्गों की हालात देश में यह हो गई है कि उनको जीवन जीने में कठिनाई हो रही है। 27 परसेंट रिजर्वेशन देने का कानून देश में बना, लेकिन वह सब प्रदेशों में लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ प्रदेशों में तो इस आरक्षण की व्यवस्था का लाभ मिला, लेकिन बाकी प्रदेशों में नहीं मिला है। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि देश में कम से कम सात ऐसे प्रदेश हैं, जिनमें अभी तक पिछड़े वर्गों की सूची नहीं बनी है। इससे सदन यह अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से पिछड़े वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह देश की आधी से अधिक आबादी वाले इस समाज के बारे में कुछ सोचे। इनको इनकी आबादी के हिसाब से बजट में धनराशि का आवंटन करे। पिछली सरकार ने जाति आधारित जनगणना करने का कार्य प्रारंभ किया था, जिसे वर्ष 2013 में पूरा होना था, लेकिन उस जनगणना का क्या हुआ, मालूम नहीं। क्या वित्त मंत्री जी इस पर टिप्पणी करेंगे?

महोदय, हमें देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं सामान्य वर्ग के गरीबों की ही चिंता करनी चाहिए... और सच तो यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यक आज अपने आपको देश के कुछ कटा-कटा सा महसूस कर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर मुस्लिम समाज की बात कहूं तो चाहे यू.पी.ए. की सरकार रही हो या एन.डी.ए. की, दोनों ने इनकी अनदेखी की है।

सच्चर कमेटी रिपोर्ट एवं रंगनाथन रिपोर्ट कब सरकार के सामने आयी और अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हुआ है? सारा देश इस बात को जानता है कि सच्चर कमेटी में इस बात का जिक्र हुआ है कि धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति दलितों से भी बदतर है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की है। फिर सरकार क्यों नहीं जागती? हमारी पार्टी इस मत की भी समर्थक है। यह सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों और सामान्य जाति के गरीबों को आरक्षण देने का कोई प्रावधान करती है तो हम सबसे पहले उसका समर्थन करेंगे। अंत में, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपील करता हूं कि देश के नौजवानों एवं किसानों को हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह वह वर्ग है जो देश के लोकतंत्र को चलाता है। अतः मेरी सरकार से अपील है कि इस बजट में आवश्यक संशोधन करके जो तथ्य मैंने अपने भाषण में रखे हैं, उन्हें शामिल करें और देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए जीने के नए रास्ते खोलें। धन्यवाद। जय भीम।

श्री उपसभापति : श्री हरिबंश नारायण सिंह Maximum 15 minutes.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : उनकी मेडन स्पीच है।

श्री उपसभापति : मेडन स्पीच है इसलिए 15 मिनट का समय दिया है।

श्री हरिवंश (बिहार) : सर, आप जब कहेंगे, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि मेरी बात को आप पहली बार सदन में रखने दें। माननीय उपसभापति जी, मैं सबसे पहले आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्मानित मंच से मेडन स्पीच देने का मौका देने के लिए। आपके और हमारी पार्टी जनता दल (यू) के नेता माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय शरद जी के सौजन्य से मुझे यह अवसर मिला है, इसलिए पुनः आभार के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सर, मैं आरम्भ में स्पष्ट कर दूं कि बजट बनाने के लिए मौजूदा सरकार को बहुत कम समय मिला। कुछेक उल्लेखनीय चीजें उन्होंने जरूर की हैं, गांवों में, स्कूलों में टॉयलेट्स बनाने के लिए धन का अच्छा आवंटन किया है, अधिक किया है। इसका हमें अहसास है, लेकिन रचनात्मक आलोचना का मकसद यह है कि सरकार अपने दिखाए सपनों की राह से न भटके। इसलिए इनके हित में मैं आलोचनात्मक मूल्यांकन करूंगा। चुनाव में प्रचार के बल पर आपने जो माहौल बनाया, उससे लगा कि एक नयी सुबह दस्तक दे रही है। हिन्दी के एक बड़े कवि हुए, मुक्तिबोध, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आयीः

"एक पांव रखता हूं तो हजार राहें फूट पड़ती हैं।"

लगा कि किसी समाज और देश के जीवन में यह घड़ी कभी-कभी आती है, जब हम ऐतिहासिक बदलाव के दरवाजे पर खड़े होते हैं, लेकिन Budget is the most important economic instrument of political ideology. आपके बजट के आने के बाद क्या हुआ? उन राजनैतिक सपनों को साकार करने का सबसे प्रभावी कारगर माध्यम तो आपका बजट ही था, लेकिन बजट के बाद जो लोग उम्मीदों के शिखर पर छलांग लगा रहे थे, उन विशेषज्ञों की चार टिप्पणियां, मैं आपके माध्यम से यहां रखना चाहूंगाः Chidambaram Budget with saffron lipstick; Modi's too safe Budget; Jaitley dons a PC mask; "UPA-III Budget. ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए कि आपकी राजनीति के अनुरूप आपका आर्थिक दर्शन साफ नहीं है। इतिहासकार टायनवी ने कहा था कि भविष्य के लिए इतिहास दृष्टि देता है। मुझे लगता है कि हमारे इधर बैठे लोग अपना इतिहास भूल गए। वे दीनदयाल जी की बात करते है, "एकात्म मानववाद" की बात करते हैं। 1963 में उनकी "भारतीय अर्थनीति-विकास की दिशा" नामक पुस्तिका आयी थी जिसके आधार पर दत्तोपंत ढेंगड़ी जी ने तब कहा था कि "न पूंजीवाद, न समाजवाद, बल्कि तीसरा रास्ता हम चाहते हैं।" 1980 में आपने पंचनिष्ठा अपनाई, गांधीवादी समाजवाद की बात की, उसके बाद आपने स्वदेशी की चर्चा की और उसमें कहा कि तकनीक बाहर से आएगी, बाकी सारी चीजें हम खुद करेंगे, लेकिन ये सब चीजें अपने अतीत में करते हुए आज आप एफ.डी.आई. में मुक्ति का रास्ता देख रहे हैं। आप में वैचारिक स्पष्टता नहीं है, आपकी इकोनॉमिक फिलॉसिफी साफ नहीं है। संदेश तो साफ है। आप और अधिक निजीकरण की ओर जाना चाहते हैं, और बाजारवाद को लाना चाहते हैं लेकिन देंग सियाओं पेंग की तरह आपमें यह कहने का साहस नहीं है कि बिल्ली काली हो या सफेद, वह चूहे को पकड़ने की ताकत रखती है यानी आर्थिक विकास का रास्ता यह है। दूसरी ओर इस देश में एक पुराना रास्ता भी था, आज

[श्री हरिवंश]

लोग गांधी के अनुयायी जे.सी. कुमारप्पा को भूल गए हैं। कभी याद करना चाहिए जे.सी. कुमारप्पा को जिनकी शताब्दी अभी हाल ही में मनाई गई। जब वे गांधी जी से मिले तो किस तरह से अमेरिकन सूटेड-बूटेड व्यक्ति के रूप में थे और गांधी के इकानॉमिक थॉट के सबसे बड़े चिंतक के रूप में वे सामने आए और उनकी पुस्तक 'Capitalism, Socialism or Villageism थी। 'Economy of Permanence' उनकी दूसरी किताब थी। इन्होंने भी तीसरे रास्ते की तलाश की थी। हमारी दाहिने तरफ बैठे लोग, जो गांधी के वारिस रहे, वे 1991 में गांधी का रास्ता भूल गए। शायद उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। स्पष्ट है कि इन लोगों ने भी तीसरे रास्ते की तलाश छोड़ दी और आपने तो छोड़ ही दी। आप दोनों आज वैचारिक धरातल पर एक जगह खड़े हैं। मार्केट इकोनॉमी के धरातल पर खड़े हैं। इसलिए बात हो रही है कि यह इधर का, यू.पी.ए.-3 का बजट है या एन.डी.ए. का बजट है।

मित्रो, इतिहास बनाने का मौका कभी-कभी मिलता है। मैं मानता हूं कि आपके पास इतिहास बनाने का मौका था। आज 1991 के बाद हालात बदल गए हैं। 1991 में मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही थी, आज समाज ही बाजार बन गया है। मार्केट इकोनॉमी and being a मार्केट सोसायटी, दोनों में फर्क है। मैं दो किताबों का उल्लेख करना चाहूंगा जिस पर आज दुनिया में आर्थिक विकास का मॉडल क्या हो, इस पर बहस चल रही है, 'The Power of less' यानी कम से कम साधन में हम कैसे खुशी से रह सकें और दूसरा 'The Moral Limits of Markets'. मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि एक महात्मा ने हमें आजादी दी, उस व्यक्ति के विचार को आज दुनिया अपना रही है और आपने यह मौका गंवा दिया और आप किस राजनीति की ओर चल पड़े? मैं मानता हूं कि राजनीति की दो धाराएं हैं। पहला मैक्यावेली, जिन्होंने कहा था, "अतीत में किया गया वायदा तब की राजनीतिक जरूरत थी, वर्तमान में वायदाखिलाफी आज की राजनीतिक जरूरत है।"

मित्रो, मैक्यावेली ने 15वीं शताब्दी में कहा कि साधन और साध्य का कोई अर्थ नहीं, किसी तरह से सत्ता पाओ, कुछ भी कहकर पाओ, लेकिन एक व्यक्ति 400 वर्षों बाद हुआ, जिसने कहा कि नहीं। महात्मा गांधी ने साधन और साध्य को एक नई दिशा दी और लालबहादुर शास्त्री के बाद से कांग्रेस उससे भटकने लगी। इससे समाज में राजनीति की साख पर संकट आया, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया है आपने सरकार बनाते वक्त जो वायदे किए थे, उस पर न चलकर उस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को राजनैतिक संस्थाओं के प्रति, राजनैतिक दलों के प्रति और बढ़ा दिया है। यह नि ष्कर्ष किसी दुर्भावनावश नहीं है। मैं न अर्थशास्त्री हूं, न विशेषज्ञ हूं, मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा ग्रासरूट लेवल पर गांव, देहात, जंगल, पहाड़ों में पत्रकारिता करते हुए गुजरा है। सर, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि आपके घोषणापत्र में क्या था और आपके बजट में क्या है। घोषणापत्र में शिक्षा पर सरकारी खर्च को बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी करने का उल्लेख है। यह पेज नम्बर 36 पर है। साथ में कहा गया कि इसमें निजी क्षेत्र को जोड़ कर इस खर्च को और बढ़ाया जाएगा, जबकि बजट में आवंटन साढ़े तीन फीसदी के आसपास है। कहने और करने में पहला फर्क यह है। घोषणापत्र में कहा गया था कि ऐसे कदम उठाये जायेंगे, जिनसे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 प्रतिशत लाभ हो। यह घोषणापत्र के पृष्ठ 44 पर है, जबकि इस पर बजट पूरा चुप है। बजट में

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई चर्चा नहीं है और न ही स्वामीनाथन कमेटी का कोई उल्लेख है। कृषि क्षेत्र में कैसे बेहतर ग्रोथ हो, इस दिशा में आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है।

आज देश में हरित क्रांति की जरूरत है। पहली हरित क्राति पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में आई थी, लेकिन दूसरी हरित क्रांति पूर्वी भारत में लाने की जरूरत है, जहां पानी ज्यादा है। यह इलाका बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है। यहां फ्लड कंट्रोल पर करोड़ों रुपये खर्च करना अकेले राज्य सरकारों के वश की बात नहीं है। बिहार जैसे राज्य में पड़ोसी देश से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के कारण भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। इसलिए केन्द्र सरकार को आगे बढ़ कर राज्यों को सहयोग देना चाहिए। इतना ही नहीं इन राज्यों में भंडारण की सुविधा भी नहीं है। गोदामों के अभाव में पूर्वी भारत के राज्यों में बड़ी मात्रा में साग-सब्जी बरबाद हो जाती है, जिससे किसानों को घाटा होता है।

आपने अपने घोषणापत्र में कहा था कि कम पानी से सिंचाई की तकनीक को बढ़ावा देने और पानी के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की कोशिश की जाएगी। सर, यह मैं कोट कर रहा हूं। यह पेज नम्बर 44 पर है। बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें पूरे देश के लिए सिर्फ 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि सिर्फ पंजाब की ही मांग 7200 करोड़ रुपये की है। तीसरा, घोषणा पत्र में आपने कहा कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। यह पृष्ठ संख्या 47 पर है। इस मद में किसी राशि का आवंटन नही है। घोषणा पत्र में आपने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समूह, विशेषकर मुस्लिम समुदाय लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। आधुनिक भारत समान अवसर वाला होना चाहिए। धार्मिक नेताओं से बातचीत करके वक्फ बोर्ड को और मजबूत किया जायेगा, यह पृष्ठ संख्या 27 पर है। आपने मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। यह आवंटन समान अवसर देने के आपके वायदे को पूरा नहीं करता है। देश की करीब 20 फीसदी आबादी की बेहतरी के लिए यह धन पर्याप्त नहीं है। सर, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन समय कम होने के कारण मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। आपने बजट में कहा क्या और किया क्या? मैं माननीय वित्त मंत्री जी के 10 जुलाई के भाषण के एक अंश का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा 'भारत के लोगों ने निर्णायक रूप से परि वर्तन के लिए वोट दिया है। यह निर्णय लोगों का यथास्थिति के प्रति गुस्सा दर्शाता है। भारत निस्संकोच रूप से विकास करना चाहता है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति स्वयं को गरीबी के श्राप से मुक्त कराने के इच्छुक हैं। जिन्हें जटिल चुनौतियों से उभरने का मौका मिल गया, वे आकांक्षावान हो गए हैं। वे अब नव मध्य वर्ग का हिस्सा होना चाहते हैं। यह राष्ट्र बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, अवसंरचना के अभावों में उदासीन अभिशापों को झेलने के मूड में कतई नहीं हैं।'' मैं पूछना चाहता हूं कि नई उम्मीदों को पैदा करने वाली सरकार ने क्या बदलाव किये हैं? बजट में साफ है कि सरकार ने निजी क्षेत्र के विकास पर तो काफी गहराई से सोचा है, लेकिन यह बात सोशल सेक्टर पर लागू नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, फूड सब्सिडी पर सही अर्थों में खर्चे घटेंगे, क्योंकि मुद्रास्फीति और महंगाई की दर दस फीसदी रही है, परंतु उस अनुपात में सामाजिक क्षेत्र के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कितना आवंटन बढ़ा है?

[श्री हरिवंश]

आज इलाज कराना सबसे महंगा काम है। अस्पताल उद्योग बन गए हैं। दुनिया के प्रमुख देश तकरीबन पांच फीसदी बजट आवंटन स्वास्थ्य के लिए रखते हैं, परंतु हम डेढ़ फीसदी से आगे नहीं बढ़ पाए। अभी दे दिन पहले मैंने एक खबर देखी, जिसमें हकीकत यह है कि आज एक नेता या अफसर पर होने वाला सालाना स्वास्थ्य खर्च 5000 रुपये है, जबकि ग्रामीण पर यही खर्च 180 रुपये है। इस विषमता का हल बजट में नहीं है।

हमने बजट में आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे संस्थानों के लिए तो प्रावधान किया है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत कम आवंटन किया है। हम शिक्षा के गिरते स्तर को दोष नहीं देते हैं, पर दुनिया की मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहां से निकल रहे 70 फीसदी एम.बी.ए. और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को अनइम्प्लायेबल कहती हैं। हमारा शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि हम अनएम्प्लायड लोगों की एक लंबी कतार खड़ी कर रहे हैं। समाज में जे.सी. बोस, पी.सी. राय, सी.वी. रमन, रामानुजम जैसे लोगों की संख्या घट रही है क्योंकि हम सेंटर आफ एक्सीलेंस नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं हैं, उनमें हमारी संस्थाओं की गणना नहीं हो पा रही है। सरकारें लगातार नए IITs और IIMS तो खोल रही हैं, पर क्या आपने या पिछली सरकारों ने कभी गौर किया कि उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक कहां से आएंगे? बहुत जगहों पर तो आठ-दस साल पहले हुए फैसलों के बावजूद आज तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशन्स काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां ह्यूमिनिटीज और नॉन-ह्यूमिनिटीज, दोनों विषयों में अच्छे शोध करने वाले लोग, अच्छे अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। आप IITs, IIMs खड़े कर रहे हैं, जबकि वहां पढ़ाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। गरीब आखिर कहां जाएंगे? अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी हो, गंभीर इलाज कराना हो, शहरों में सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करना हो, तो इसके लिए आखिर गरीब कहां जाएं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की है, पर आपने बजट में गरीबों के लिए क्या किया है? मैं देश के पूरब के हिस्से से आता हूं। आपने अपने घोषणापत्र में पूरब के पीछे छूट गए राज्यों को भारत के आगे बढ़े राज्यों के समकक्ष लाने के लिए विशेष पैकेज और सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद ओडीशा, बिहार, बंगाल, झारखंड या उत्तर पूर्व के राज्यों को कोई विशेष दर्जा नहीं मिला है? विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक पर या आर्थिक विकास की दृष्टि से ये इलाके बहुत पीछे छूट गए हैं। केन्द्र सरकार के भेदभाव के कारण सबसे अधिक गरीब इन्हीं इलाकों से हैं। आम बजट हो या रेल बजट, इसमें सबसे ज्यादा आवंटन पश्चिम के राज्यों को मिलता है। इससे साफ है कि जो पहले से प्रभावी है, उद्यमी हैं, सक्षम है, यह बजट उन्हीं की चिंता करता है, जो गरीब हैं, पीछे छूट गए हैं, उनकी चिंता नहीं करता है।

बिहार जैसे इलाकों को पिछड़ा कैसे रखा गया, इसको बताने के लिए मैं अतीत में नहीं जाना चाहता हूं, पर इसी सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने शुक्रवार को प्राइवेट मेम्बर बिल के संदर्भ में बिहार के पिछड़ेपन को वहां के मानस से जोड़ा था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आर्थिक पक्षपात और भेद करने वाली नीतियों का इतिहास पलट लीजिए, आपके समक्ष तथ्य साफ हो जाएंगे।

फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेकर दूसरे देशों में आने वाली बाढ़ ने भी बिहार जैसे राज्यों को तबहा किया, लेकिन जब उसी बिहार को अवसर मिला, तो उसने क्या कर दिखाया। रंगराजन कमेटी का आकलन है कि बिहार में 2009-10 से लेकर 2011-12 के बीच, गरीबी का अनुपात, महज दो वर्ष में एक-तिहाई कम हुआ। महज दो वर्ष में भारत के अन्य किसी राज्य के मुकाबले यह सबसे तेज गति से कम हुआ हैं। अब तक सबसे अधिक गरीब बिहार में रहते थे, लेकिन इस रिपोर्ट के अब अनुसार छत्तीसगढ़ में है। हिन्दुस्तान टाइम्स में 8 जुलाई, 2014 को प्रमुखता से यह खबर छपी है - Bihar records highest dip in poverty ratio. मैं याद दिलाना चाहूंगा कि साठ के दशक में प्रमुख चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक सच्चिदाबाबू ने किताब लिखी थी कि कैसे बिहार को इंटरनल कालोनी बना दिया गया। उसको ठीक करने के लिए एक व्यक्ति, श्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया। उन्होंने विशेष राज्य का अभियान चलाया। इसके लिए उन्होंने सवा करोड़ लोगों से दस्तख्त लेकर कोशिश की, परंतु हालात वही रहे। आज बिहार की क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूंगा कि यदि बिहार मॉडल के पीछे कोई कारपोरेट ताकत होता तो आज यह दुनिया में जाना जाता, क्योंकि बिहार ने पांच वर्षों में जो समावेशी विकास किया है, वह शायद देश में अन्य किसी राज्य ने न किया हो। पर बिहार को हमने कहां छोड़ा? आज जब मैं पटना में दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ जाता हूं, तो मुझे सिर्फ एक पुल दिखाई देता है। आप दूसरे राज्यों में चले जाएं, तो क्या हालात हैं, क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है। पूरी गंगा पर साउथ से नॉर्थ जाने के लिए बिहार में 66 वर्षों में चार पुल बने। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can have two more minutes.

श्री हरिवंश : बिहार सरकार छह और पुल स्वयं बना रही है। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के भेदभाव की नीति का अंत किया जाए, तो शायद देश में हालात बदलें।

माननीय उपसभापति जी, मैं कुछ और चीजों की चर्चा करना चाहूंगा, जो आज देश समाज और व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आज दुनिया की आबादी का 17.5 फीसदी हिस्सा भारत में है, जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से हमारा प्रसार दुनिया के 2.4 फीसदी हिस्से में है। 3-4 वर्ष पहले केसरोली ग्रुप से जुड़े एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट दी थी - इंडियाज डेमोग्राफिक सुनामी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक भारत में शहरी आबादी 23 फीसदी से बढ़ कर 40 फीसदी हो जाएगी, यानी हम 28.5 करोड़ से 54 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। अगले 25 वर्षों में अनुमान है कि देश की आबादी 35 करोड़ तक बढ़ सकती है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न की स्थिति, नौकरियों की संख्या, घरों की संख्या, बिजली, सड़क, इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति के बारे में कोई फ्यूचर प्लान नहीं है।

सर, मैं अगली बात युवकों के रोजगार के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे पास चार तथ्य हैं। इन चारों आंकड़ों से यह निकलता है कि आज काफी बड़ी संख्या में हमारे 10-15 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, पर उनके लिए कोई नया रास्ता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है, ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक तरफ ग्रासरूट लेवर पर ये कठिन चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति दिख रही है। हम किसानों की आत्महत्या की तो बात करते हैं, पर मामूली उद्यमी, जो बैंकों से लोन लेकर अपनी जिन्दगी में नया बदलाव चाहते हैं,

[श्री हरिवंश]

ऐसे लोग भी बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। इस जुलाई के प्रारम्भिक सप्ताह में एक बड़ी खबर छपी। ...(**समय की घंटी**)...

श्री अली अनवर अंसारी : सर, इनको दो मिनट और दे दीजिए, यह इनकी मेडन स्पीच है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : How can I manage time? There are so many speakers.

श्री हरिवंश : सर, आप मुझे दो मिनट और बोलने की इजाजत दे दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Maiden speech is for fifteen minutes.

श्री हरिवंश : सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज नौजवानों में अपने फेल्योर से आत्महत्या करने प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह मार्केट इकोनॉमी की देन है। कभी ब्रिटेन में ये हालात हुए थे, तो ब्रिटेन की संसद ने इस पर एक समिति बनाई कि क्रेडिट कार्ड जनरेशन की स्थिति क्यों हो रही है। आज अपने देश में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, बल्कि आगाह करना चाहूंगा कि इस देश में तेजी से जो आर्थिक विषमता बढ़ रही है, उसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। 1991 देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हमने लाइसेंस-कोटा-परमिट राज से, यानी कंट्रोल्ड इकोनॉमी से उदारीकरण की व्यवस्था को अपनाया। लेकिन इसके दो सिम्बल्स साफ दिखाई दिए - आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय विषमता। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं। दुनिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब आई है, जिसकी सारे पॉलिसी मेकर्स चर्चा कर रहे हैं - कैपिटल इन ट्वेंटी फर्स्ट सेचुरी। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक दो सौ वर्षों में पूंजी का मूवमेंट कैसा रहा, इसमें इसका अध्ययन है, भारत का भी है। उसके लेखक जाने-माने अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत के शीर्ष एक फीसदी अमीरों के पास राष्ट्रीय आय का 8 से 9 फीसदी हिस्सा है। यह आर्थिक विषमता गहराई से बढ़ रही है।

सर, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहूंगा, पर दो चीजें, और कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, जिसके लिए आप मुझे इजाजत दें। इस बजट के बारे में मेरी टिप्पणी वही है, जो कभी वेंकैया नायडु जी ने तत्कालीन सरकार के बजट पर पिछले साल 2013-14 के भाषण में कहा था - "Broken promises and token allocations; words for the poor and deeds for the rich." दूसरी बात, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा - "pro rich and pro poor". पर क्या व्यवहार या लोक जीवन में यह उतरता है? 19 जुलाई को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपी कि भारत में डॉलर बिलियनेयर्स की संख्या पिछले साल 46 से बढ़ कर 56 हो गई है। एक वामपंथी अर्थशास्त्री मित्र कहते हैं ...(**समय की घंटी**)... कि 13 लोगों की संपदा 80 करोड़ लोगों के बराबर है। यह आर्थिक विषमता देश में नया सामाजिक तनाव पैदा करेगी। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. आर. लक्ष्मणन, आपके पास पन्द्रह मिनट हैं। ...(**व्यवधान**)... That is why I said "fifteen minutes." If it's not maiden, then you would get only five minutes. Since it is your maiden speech, you will get fifteen minutes.

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Sir, I rise to make my maiden speech on the Union Budget 2014-15. This being my maiden speech, it is my duty and responsibility that I acknowledge gratefully my leader hon. Amma who has sent me to this temple of democracy.

Man is a social animal. It is his social relation with other human beings that gives meaning to his existence. How can life be without relations? Of all the relations man has created for a meaningful living, it is the relationship and the emotional bond between mother and her children that is most unique, sacred, holy and everlasting. Mother is the source of life, reason for existence, and a mother is God personified. My mother whom we affectionately refer to as *Amma* is the source of my life and the reason for my being here. Without our leader, hon. *Amma,* an ordinary son of a peasant family cannot ever dream of entering, this pinnacle of democracy, the Parliament of this country. Standing here, I respectfully pay my salutations to our hon. *Amma,* whom the whole of India now refers to as Amma, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, the General Secretary of my Party, I will eternally be loyal and grateful to *Amma's* grace and blessings on me.

At this moment of joy, I fondly remember the love and care of my parents, my beloved wife and children, especially I recollect the contribution of my teachers in Sacred Heart School, Villupuram, and my medical UG and PG professors in Annamalai University, my friends and Party cadre, and my colleagues in the Parliament are also reason for me standing here now.

Sir, now, I come to the Union Budget presented by the hon. Finance Minister. First of all, I congratulate the Leader of our House for presenting the first Budget of Shri Narendra Modi-led Government. I recognise that he had just a few weeks to prepare the Budget and he has inherited ten years of financial anarchy primarily aimed at elections.

The previous UPA Government of Congress-DMK combine pushed India to unprecedented corruption. History will always remember the worst ever corruption man could perform, which is the 2G spectrum allocation scam. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, what is he speaking? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, there should not be any interruption. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): History cannot be deleted. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not taken any name. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: What is this? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, he has not mentioned any name. ...*(Interruptions)*... He did not take any name. ...*(Interruptions)*... He only mentioned about corruption. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, let it be about the Budget. ...*(Interruptions)*... Sir, I know that under Rule 238A, any Member should talk only on the subject. Kindly refer to that. ...*(Interruptions)*... Sir, it is a point of order. ...*(Interruptions)*... I don't want to interrupt his maiden speech. ...*(Interruptions)*... Please instruct him not to create any controversy. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Siva, please take your seat. ...*(Interruptions)*... You sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, you sit down. ...*(Interruptions)*... I will deal with that ...*(Interruptions)*... Dr. Maitreyan, please sit down. ...*(Interruptions)*... Mr. Siva, you are a Vice-Chairman. ...*(Interruptions)*... You please listen. ...*(Interruptions)*... This is a discussion on the Budget. Corruption can be discussed. The only thing is that names should not be taken. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: He has taken the name of my Party. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: You were a part of the Government. ...*(Interruptions)*... Your Party was in the Government. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Then, I should also take the name of their Party and their leader. ...*(Interruptions)*... Who started corruption? ...*(Interruptions)*... How many cases are there? ...*(Interruptions)*.... For 15 years, they are dragging cases. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAIN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: They are silent spectators. So, we are speaking. ...*(Interruptions)*... He is accusing you also. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: They got a bad name because of you. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAYA SINGH (Madhya Pradesh): Sir, it's a maiden speech of the hon. Member. He should also be very careful about the words he chooses.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a good advice for you.

DR. V. MAITREYAN: We choose our words very carefully.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Lakshmanan, do not go to controversial issues. If you speak on the Budget that will be better for you.

DR. R. LAKSHMANAN: The destruction of the Congress Party and decimation of the Congress Government was caused by the 2G Spectrum scam and many scams followed after that which threw India to a miserable financial situation.

It is indeed a difficult task for any Government to set a new path and I am happy the Government under the leadership of hon. Shri Narendra Modi has taken some specific initiatives through this Budget to bring in financial recovery. I wish him all the best.

Now I will come to specifics. I thank the hon. Finance Minister for the smart cities concept he has announced and he has given one such city to Tamil Nadu, at Ponneri near Chennai.

While replying I expect the Finance Minister to enlighten the House what he means by 'Smart Cities' and what will be the quantum of investment for each city.

A substantial amount of Rs.2,037 crores have been allocated in the present Budget for cleaning and conservation of River Ganges and another Rs.100 crores have been set aside for beautifying select river fronts; no doubt River Ganges on the banks of which the Indian civilisation thrived needs to be cleaned and conserved. But, at the same time, water needs of States like Tamil Nadu should be immediately attended to. Sir, Tamil Nadu does not have any perennial rivers. Our lifetime rivers originate elsewhere and flow through our State. It is a matter of great urgency that initiatives are taken to interlink Indian rivers. Tamil Nadu is highly dependent on water from the Cauvery River for irrigation and drinking purposes. The Government of India should allocate, at least, a portion of the money to strengthen the banks of the Cauvery River.

Sir, I see Agriculture, IT, Textile industry, Medical and Tourism are major sources of income and employment for modern India. I am happy that new textile parks will be created in several places of our country, and one such is going to come up in Tamil Nadu. Actually the real problem lies in the competition faced by the Indian textile industries from Chinese industries. The textile industries of our country can be saved only through revolutionary initiatives to modernise and liberalise the laws of the textile industry. I am sure the Government of India is aware of the enormous growth in the textile industry of Bangladesh, our small neighbour. It is time we wake up to the reality and save our own textile industry.

Inflation and price rise in India is the major concern for policy makers like us. It is appropriate for me to mention about the measures taken by my Hon'ble Leader Amma

1.00 P.M.

[Dr. R. Lakshmanan]

to protect the common man from inflation and price rise. Throughout Tamil Nadu my leader Puratchi Thalaivi has started Amma Unavagam, that is, Amma Canteens, wherein idly is being sold at Re 1, two chapathis and a cup of dhal is being sold at ₹ 3, Sambar rice is being sold at ₹ 5 and Curd rice is being sold at Rs.3. Along with this, purified water is being given free of cost. The Government of India should come forward to subsidise the State Government of Tamil Nadu in the Amma Unavagam initiative. The fluctuating cost of onions has been the reason for fall and rise of the Governments in this country. In Tamil Nadu, hon. Amma has started Pannai Pasumai Kaikarigal Stores, that is, farm fresh vegetable stores, where the Government itself procures directly from farmers and sells at a very reasonable price to the people. I suggest that the Government of India studies the initiatives of hon. Amma and come forward with additional support. We must expedite the recovery of huge bad loans given by the Government owned banks to the big borrowers in our country. Maybe, you should empower the Department of Recovery Tribunals for speedy realisation of bad loans. We should also act on a war-footing to bring back the black money kept by Indians in foreign banks.

I welcome the idea mentioned in the Budget that MGNREGA will become an exercise of asset creation. But I do not know how you are going to do it. An explanation from the Finance Minister is keenly awaited.

Lastly, Sir, I read in a newspaper that like how Deng Xiaoping changed China, hon. Shri Narendra Modi may change India and lead this nation towards peace and prosperity. I wish the prediction of that newspaper comes true sooner than later so that billions of our countrymen could eat well, dress well and sleep in a safe and secured home. Long live India. With these words, I welcome the Budget presented by the hon. Finance Minister. Thank you.

श्रीमती झरना दास बैद्य (त्रिपुरा) : सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

सर, मैं जानती हूं कि इस मुश्किल घड़ी में जनहितकर बजट पेश करना बहुत मुश्किल है, फिर भी देश की जो जनता है, उसको बड़ी उम्मीद थी कि यह सरकार कुछ तो करेगी, लेकिन सर, बजट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। एक बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कैम्पेन में बी.जे.पी. ने बहुत सारे वायदे किए थे कि जनता के हित में बहुत सारे काम करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं। वायदा किया है तो वायदा निभाना भी होगा।

[**उपसभाध्यक्ष** (**डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन**) पीठासीन हुए]

सर, चूंकि मैं नॉर्थ-ईस्ट रीजन से आती हूं, इसलिए सबसे पहले मैं नॉर्थ-ईस्ट के बारे में ही बोलना चाहती हूं। आप जानते हैं, 1952 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी भी

सरकार ने इन 8 स्टेट्स के लिए कभी कुछ नहीं किया है। पहले इसमें 7 स्टेट्स थे, अभी 8 स्टेट्स हैं।

उत्तरी पूर्वांचल के लिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा-बहुत तो दिया है, लेकिन नया कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में बहुत सारे नैचुरल रिसोर्सिज हैं, जैसे गैस, रबर, टी, everything is there. लेकिन यह सरकार, जो अभी जवान है, उसने नॉर्थ-ईस्ट के लिए कोई भी नया पैकेज नहीं रखा है। पिछली सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए '15-प्वाइंट प्रोग्राम' रखा था, हालांकि उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन आपने तो कुछ रखा भी नहीं है। एक भी प्रोजेक्ट या एक भी स्कीम इस बजट में नॉर्थ-ईस्ट के लिए नहीं है।

सर, आप जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में ब्रह्मपुत्र ऑपरेशन स्लोगन उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, क्योंकि जवानों के सामने कोई और रास्ता नहीं है। काम करने के लिए वहां कोई फैक्ट्री नहीं है। वहां तक अभी रेल भी नहीं पहुंची है। असम को छोड़कर बाकी जो 7 स्टेट्स हैं, वहां तक अभी रेल नहीं पहुंची है। हालांकि त्रिपुरा में मीटर गेज शुरू हुई है, लेकिन कुमारघाट से अगरतला तक और अगरतला से सबरुम तक जो नई मीटर गेज लाइन बन रही है, उसे ब्रॉडगेज लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने कितनी ही चिट्ठियां लिखी हैं, कितने ही आवेदन किए हैं, लेकिन वहां के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।

वहां बेरोजगारी है। दिन-पर-दिन बेरोजगारों की संख्या और अधिक बढ़ रही है, इसलिए वहां के जो जवान हैं, वे विप्लवगामी हो रहे हैं। वहां पर उग्रवाद की समस्या है, यह बात आप लोग जानते हैं और उग्रवाद वहां और अधिक बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नॉर्थ-ईस्ट के बारे में कुछ सोचना चाहिए और वहां के लिए कोई नया पैकेज देना चाहिए। वहां के जो नेचुरल रिसोर्सिज हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं महिलाओं के बारे में भी कुछ बोलना चाहती हूं। आपने महिलाओं के लिए इस बजट में क्या दिया? इलेक्शन के समय सब पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को मम्मी, दादी, बुआ, चाची कह-कह करके वोट ले लेती हैं और बहुत कुछ करने के वायदे कर देती हैं। बहुत कुछ करने का वादा करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वह पूरा नहीं होता है। अभी आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन इससे पहले ही आप लोगों ने महिला के ऊपर बुलेट ट्रेन चला दी। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया गया, मात्र सौ करोड़ रखा है। पूर्व वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने निर्भया फंड के लिए एक हजार करोड़ रुपए रखे थे और महिला बैंक खोला था। इस बजट में निर्भया फंड के लिए कुछ नहीं है। नया कुछ दिया है, लेकिन नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलेंगे, तो क्या होगा, स्कीम तो एक ही है न? आपने फिफ्टी-फिफ्टी कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। जब आप लोग इधर बैठते थे, तो बहुत कुछ बोलते थे, अब आप उधर बैठे हैं यानी सत्ता में आ गए हैं, तो सब भूल गए? यह तो हो नहीं सकता है। यह कैसे होगा?

सर, मैं मिड-डे मील वर्कर्स 'आशा' के बारे में बोलना चाहती हूं। वे सभी महिलाएं हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्कर्स कान्फ्रेंस में सब लोगों ने इस पर सहमति जताई थी कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया है। यह क्यों नहीं किया गया, हम लोग नहीं जानते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mrs. Baidya, your party's allotted time is over.

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रही हूं। 1975 से ऑनरेरी वर्कर्स पूरे देश में काम कर रही हैं। वे लोग हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करने के काम में लगी हुई हैं। वे लोग जन्म-मृत्यु का रजिस्टर मेंटेन करती हैं, घर-घर जाती हैं, प्रेगनेंट औरत को देखती हैं, बच्ची को देखती हैं, बच्ची को तैयार करती हैं, लेकिन उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता है। 'आशा' वर्कर्स सब कुछ करती हैं, इनके ऊपर सामाजिक दायित्व है। हम लोग इस संबंध में पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद जी से जाकर मिले थे। उन्होंने कहा कि उनको पांच सौ रुपए ऑनरेरियम देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया गया। उनको इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि वे औरत हैं? आप लोग इनसे काम करा सकते हैं, लेकिन कुछ दे नहीं सकते हैं, यह तो हो नहीं सकता है। हम यह करने नहीं देंगे। सर, अब मैं एस.सी. एवं एस.टी. के बारे में बोलना चाहती हूं। उनके वोट के बिना आप लोग सत्ता में नहीं बैठ सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have to conclude now and kindly address the Chair.

श्रीमती झरना दास बैद्य : सर, एस.सी./एस.टी. के लिए जो प्रावधान था, उसको भी इस बजट में कम किया गया है। हर साल इसमें कटौती हो रही है। यह कटौती क्यों हो रही है? वे लोग कुछ कर सकते हैं। इस देश के जो एस.सी., एस.टी., माइनॉरिटी, ओ.बी.सी. हैं, इन सब लोगों ने मिल कर आपको सत्ता में बैठाया है, यह आपको याद रखना होगा। इसलिए हम यह चाहते हैं कि बजट में इनकी मद में जो कटौती की गई है, उसको बढ़ा दिया जाए। प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार यह करना चाहिए, आप अपनी मर्जी से इसको नहीं कर सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You better address the Chair. Then, you can finish quickly. If you look at other parties, then, you will have emotional features.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, I would conclude by saying that the Budget, essentially, fails to chart a trajectory to increase growth and investment, create employment and check inflation that are needed in the current scenario. It is a Budget relying more on privatization and foreign investment and less on innovative ideas to increase revenue. The Budget is grossly repressive and anti-people and would increase the burden on the common people.

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Thank you, Sir. I rise to speak on behalf of my State of Andhra Pradesh about the Union Budget. I rise on behalf of the State of Andhra Pradesh and our Party to support the growth-oriented Union Budget.

After a decade we are seeing this kind of a Budget which is expected to lead the economy for revival. Definitely, the Government has showcased to serve the weakest and poorest sections of our society. It will give thrust to manufacturing, infrastructure, housing, education, healthcare and irrigation. As all my learned friends are aware that after bifurcation of our State of Andhra Pradesh, both the States are in a disadvantaged position, suffering from acute power shortage, unemployment, drinking water and lack of infrastructure. Adding to that, we are all aware that this time drought is also adding to the problem. My party is confident that with the progressive policies of the NDA Government, under the leadership of Shri Narendra Modi, our newly born State will be helped by the Centre for quick development.

Sir, there is one important thing. I would like to draw the attention of this House that the Government has allocated about ₹ 150 crores for the safety of women in large cities. They have specially mentioned it; whereas we are all aware that 75 per cent of our population lives in villages, they have not spoken anything about that. I feel that they have been neglected in this Budget. Hence, I request the Government to consider allocation of more funds and give uniform justice. We also welcome the proposal of Government of having 100 smart cities across the country and I think they have allocated a Budget of about ₹ 7,060 crores. The Government is certainly going to provide fresh direction and a sense of legitimacy to a concept that has been popular, but not enthusiastically taken up. We were thinking that we would get more support from the Centre in the Budget whereas a token grant of ₹ 1,140 crores was mentioned to meet the Budget deficit of Andhra Pradesh State, though the deficit is about ₹15,000 crores. I request the Finance Minister to reconsider and address this problem with the right spirit since the bifurcation itself is done by the Government of India in an unscientific manner. So I request the Central Government to render special support to both the States, the State of Telangana as well as the State of Andhra Pradesh. Since the entire process is done without proper study of economics, how are both the States going to survive? Sir, there is a need for creating smart cities across the country. It is a long-pending issue for our nation. Otherwise, the condition of metros is really becoming a problem day-by-day. Definitely, we support this initiative. Our party supports this proposal wholeheartedly and expects from the Central Government to extend maximum financial help to the State of Andhra Pradesh while making our Capital city as well as allocating certain smart cities. They have mentioned only one Smart City whereas the State of Andhra Pradesh definitely requires, at least, more than one, if not four.

Keeping in mind about the economic upliftment of rural areas, the Central Government, in its Budget, has introduced a new scheme for village entrepreneurs with

[Shri Y. S. Chowdary]

the name Shyama Prasad Mukherji Mission for Rural Development. Schemes like skill development in India will boost the confidence of India's youth and create a massive job opportunities. Under this initiative, all metro cities can set up more skill development institutions. The Central Government has given due emphasis on education. We welcome the decision to opening up of new IITs, IIMs and Agriculture Universities in other parts of India. This is a good beginning to develop and spread education. Literacy is very important for the country's economy and for improving standard of lives.

Pradhana Mantri Gram Sinchai Yojana designed to provide irrigation facilities to rain-fed areas will not only benefit farmers but also strengthen our food security.

There is a push towards infrastructure, healthcare and water development which would make life much easier for an average citizen. New technologies are to be leveraged fully wherever it is possible.

Apart from raising public investment, there are many measures to reverse the fall in private investment and increase productivity. This is essential to reverse the slowdown in manufacturing which has totally depleted in the last one decade.

Promoting FDI in strategic sectors such as Defence production and insurance will also directly increase jobs in the country, technology and financing. The Government's proposal to disinvest and raise about Rs. 43,000 crores in the year and then Rs. 15,000 crores in the subsequent year will, certainly, help in bringing down the fiscal deficit.

A major shortcoming in the economy is high transaction costs and the possibility of unproductive arbitrage. To address this, the Union Budget has proposed a number of initiatives to reduce these, especially in the areas of tax structure and administration. There is a commitment towards transparency, simplification, to listen to and rectify complaints. The Government also mentioned that they will not amend any Acts retrospectively. It will set up a Committee to review cases arising from past amendments. There are legal and administrative changes to reduce tax litigation. Resident taxpayers can also get advance tax ruling. There are administrative provisions to ease access for them. A high-level Committee will be set up to regularly interact with industries and respond to issues raised.

In conclusion, I believe, the measures taken in the Budget will be sufficient to increase growth in the economy. And, I am confident that measures indicated in the Budget are implemented to achieve the growth of about 8 per cent.

On the whole, the Budget definitely wants to emphasis and focus on healthcare, education and employment and also by way of spending a good amount of money on skill

development. The next phase of reforms or policies to be implemented should start right now, probably, after getting stability of these policies which may be after two years. But, the work should start now, so that the blueprint is prepared properly for its implementation. This has to be done particularly by leveraging technology.

With this, I support the Budget and also the Appropriation Bill, 2014. Thank you.

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Sir, first, I would like to – though the hon. Finance Minister is not here — congratulate him on his first Budget speech to the Parliament and to the country. I also congratulate him for the continuity of many ongoing initiatives of the previous Government. This is not the time to score brownie points over each other. I think the Budget and fiscal management of the country are very important for the well-being of each and every individual in our country. Therefore, I think, we would like to be very constructive in our approach and try to see that the best can be obtained for the development and growth of our country from the outcome of the Budgetary proposals.

Sir, many schemes, as I said, have been continued, some are sought to be redefined or rechristened and some schemes have been done away with; so be it. The real issue is this. I begin first with the overall macro management of the economy.

I come to fiscal deficit. These are the words to many analysts who say as if they are the cornerstone or milestone of any budgetary exercise. Fiscal deficit which was 4.5 per cent in the last financial year is now sought to be reduced to 4.1 per cent in this financial year. Well, fiscal deficit can be controlled to whatever level one wants, but it depends on the kind of spending the Government does. Is it out of contraction of the economy you are achieving the fiscal deficit of 4.1 per cent or is it by way of better management of the economy by which fiscal deficit can be controlled? My own understanding is this. In the previous year, when the Finance Minister brought down the fiscal deficit to 4.5 per cent, it was a tight budgetary exercise. He did a lot in controlling the Government expenditure. A lot of Plan expenditure was also sought to be restricted. And, there was a conscious effort to raise more resources, both by way of direct taxes, indirect taxes as well as disinvestment of certain Government companies. Therefore, fiscal deficit was brought down to 4.5 per cent. If this year the ambition is to bring it down to 4.1 per cent, the first parameter – if the new Government really wants to give much more to the people by way of increased spending and allocating more money to schemes – should be to expand the size of the economy. If they think that 4.1 per cent is going to be achieved by reducing expenditure then, I think, it is not prudent. If that is so, then the expectations of people on the basis of which you have really come to the position of power can be belied. Therefore, I feel,

[Shri Praful Patel]

there is no significant direction in the Budget which promotes or promises that size of the economy will expand. How does the size of economy expand? It expands if there is more industrial production, if there are more goods and services, if there is more employment, if there is more agricultural production and so on. These are the signs of an expanding economy. And, when you have more money at your disposal, you spend more because you get more. But, if you manage the economy well, you can bring down the fiscal deficit. I don't see those signs. It sounds very well, as I said, to bring it down to 4.1 per cent, but it does not really appear as a conscious exercise on how the economy can be expanded. I know, a lot of constraints are there on any Government, on any new Government. Forty-five days is not a very long period of time which, I am sure, arguably nobody can deny. But, at the same time, there has to be a certain innovation of thinking to be able to achieve some of the high objectives of the goalposts which you have placed before us.

I will just mention a certain things. I have been reading and you have also been stating that prices of petroleum products or gas or other issues have been postponed by 3-4 months. On the other side, the cost of imported petroleum products has gone up because of certain incidents which took place in Iraq and otherwise. On what basis are we able, therefore, to say that the Government will be able to help the under-recovery of the oil prices for the petroleum companies? On what basis are you, therefore, in a position to say that the industrial production or other goods and services or the farm sector will increase in the short-term? In fact, thanks to the rains in the last few days; otherwise, there was a chance of going through a very bleak phase, almost, in our agriculture. However,, God seems to be very kind and, therefore, that probability can be deferred. But, the fact is that, on the whole, the economy does not show any signs of a huge revival which will be able to find a lot of schemes or issues which you have been pointing out to us.

There have been many announcements. Announcements are always very nice. I was just talking to Jayaji. We were talking about many new phrases which have catchwords, which have now caught the imagination of the people—smart cities to begin with. My friend was also speaking about smart cities. What is a smart city? I don't think anybody knows. At least, the definition of what a smart city is should have been placed before us. By saying '100 smart cities' *...(Interruptions)...*

I am not critical about any individual. You may wish to, but I will not join you. But, I will say that I would like the Budget to have said what a smart city is. If China mentions, 'We have set up a new city Guangzhou, Sheng Zhen" or many other names, I can see. What is our definition of a smart city? By simply announcing, 'I will give one smart city to Jammu and Kashmir, one smart city to Telangana and one in Andhra Pradesh', then, I think, we have not really got the concept right. I wish you expanded on that. You still

have time to give us an idea and expand on that as to what the definition of a 'smart city' is. We all know, to set up an industry of a thousand acres, to acquire land is next to impossible. Thanks to even our side of the divide when we have also promulgated a legislation along with your support to make sure that the farmer or the land owner gets the adequate price and a good compensation, but the difficulties arising out of that have also been enumerated by many people, by many State Governments, which we have not factored when we say that we will have a 100 smart cities in the next five years. What is the size of a smart city? Is it of 1,000 acres? Is it 10,000 acres? Is it 10,000 hectares? What is the definition? What all will get incorporated in a smart city? I don't think we are clear yet, at least on that. That is what we have not been able to understand out of this exercise. I wish you could elaborate on that.

Even when we talk of road and other connectivity, I think, many issues are there. I have been reading the statements of the Surface Transport Minister even as early as this morning where he says, "I am not getting anybody to come and bid for Public-Private Partnership in road projects any more." If there is a fundamental problem, that should be addressed. Okay, you said it, fine and, therefore, you would like to go in for EPC contracts. No harm as long as you find another alternative mechanism. Please continue with that way to take the project forward. But, at the same time, unless you have a PPP definition, you are not going to be able to find the money to really expand the road network you have designed it. In this year's Budget, you have given Rs.37,000 crores, which, I am sure, if you look at it in dollar terms, it is six billion dollars, for a country of our size. If you think that six biliion dollars of further roads is going to be enough for the kind of expectations which we have, I don't think it is some great money which we are talking about. Therefore, public-private-partnership is the only solution, and for that, I think, you need to look at that objective very, very meaningfully.

You have given many indications. Now, agriculture is very important, as I was talking earlier about the rains. You have provided money and reduced money, I would say, in the outlay, for *Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana.* Actually, that money which was there for the Accelerated Irrigation Benefit Programme has actually been reduced in the outlay. There is no clear-cut definition as to which was the objective and as to how you are going to use this money. Basically, all the State projects which have been getting AIBP benefits in the past, will they be continued or will you identify new projects? Simply by saying that 'yes I will allocate more money for irrigation will not fulfil the objective of the scheme'. It has to be identified. You may identify even four projects in the country and say that this will be the funding available to these four projects. It may be the Polavaram Project; it may be any other project which you can identify in the country. But there has

[Shri Praful Patel]

to be a certain, I would say, definition as to who is going to get the money out of these schemes.

You have talked about agriculture that this year you are going to achieve 4 per cent growth target. Very notable; very laudable; there is no harm. But, agriculture, I would say, in the UPA Government, has got a sustained incentive and support from Government. I have no hesitation in saying this because my leader, Shri Sharad Pawar, was the Agriculture Minister for all the 10 years, and the Government of Dr. Manmohan Singh laid special emphasis on supporting agriculture. That is the reason why in the last financial year we achieved the maximum agricultural production ever in India's history of about 269 million tonnes. The Agriculture Minister is sitting here, "I am sure, he will bear me out. When you have talked of giving ₹ 8,00,000 crores agricultural credit in this year's Budget, let us not forget that in 2004, the agricultural credit available to farmers was ₹ 85,000 crores, which in the last year expanded to ₹ 7,50,000 crores. So, that is a concerted effort of the Government of India then, and, I hope, you continue, which you are indicating that the Government would continue to give larger, larger benefit to more number of people. Unfortunately, the share of agriculiure in our GDP has shrunk to 16 per cent or 15 per cent. Of course, in any growing economy, that is bound to be the case. But unlike any other developed country, our situation is inverse in terms of more number of people which is dependent on agriculture. Therefore, we have to do much more than any other country to support our agricultural development and programmes. That is why I am happy that you are continuing the good work which we had started, and I wish that much more is done because a lot of things have to be done. In spite of all the talk which we have about food grains being rotten or wasted or agricultural produce not reaching the market and it being a perishable product, we lose that project; we need to invest much more, and we need to have a comprehensive programme. Simply by saying that perishables should be preserved and we should give more for cold storages or linkages or connectivity is not going to suffice. That all sounds very good. But what is the firm programme?

राधा मोहन सिंह जी, जब भी आप इस बारे में ध्यान आकर्षित करें, तो विशेषतः यह देखें कि कृषि का उत्पादन जितने महत्व का है, उतना ही हमें उसकी पूरी चेन को आगे बनाए रखना है। बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन उसकी गति को और बढ़ाना, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। We must be proud, you know. We talk of exports; we talk of diamond exports, leather exports and other exports. Last year, agricultural exports out of India was of 3,23,000 crores. It is not a small number. Many people even do not know that we are the largest exporters of rice in the world, we are the second largest exporters of wheat and sugar in the world, of dairy products and so many things about which India otherwise gets unnoticed. Everybody thinks India is sitting with a

begging bowl; people want to come here and sell or give to us. It is not the case any more. One of our largest items of export from India is agriculture. Therefore, we have to ensure that we are able to do that much more for the development of our agriculture.

Sir, there are many areas of concern. Now I come to power which is the lifeline of our nation. Every village you go to, every agriculturist you talk to, whichever the State right from Gujarat to Maharashtra, to any State, even in Gujarat, the agriculturists only get eight hour of power. It is not that there is 24 hours power there also. There is nothing wrong with that because there are shortages. But the fact is that we must acknowledge and how we are going to get out of this issue of shortages of power. ...*(Interruptions)*... I said it. ...*(Interruptions)*... That is exactly what I said. ...*(Interruptions)*... I will not go into that level of criticism. ...*(Interruptions)*... But I am just trying to be objective and I agree with you. I agree with you. Therefore, my limited point is that power has really hit a kind of a roadblock for various reasons. We have been accused of not having handled the power portfolio very well, we have been accused of shortages of power, we have been accused of delays due to coal availability, we have been accused due to environmental clearances, and so on. But the fact of the matter is that even today I do not see a definite roadmap as to how we are going to overcome the shortages of power and to make power much more available and much more reasonably available because the other day I was reading in the newspapers, correct me, if I am wrong, but the Power Minister was saying, "l do not have coal for more than two or three days and if the power projects need to have the coal, they can import it." It is very easy to say. The logistics of importing, the logistics of transporting coal within or from outside is not something which is so easy. The fact of the matter is that there will not be enough power or the quality of power which you want in the country. To that extent, simply by addressing certain issues on the Budget exercise....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Excuse me, would you like to continue after lunch?

SHRI PRAFUL PATEL: I go with the sense of the House. I am ready either way. Okay, after lunch.

THE VICE-CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for 30 minutes.

The House then adjourned for lunch at thirty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at ten minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Patel, didn't you finish your speech?

SHRI PRAFUL PATEL: No, Sir, two, three minutes left.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. If you have not finished, then, how much time is left.

SHRI PRAFUL PATEL: Mr. Deputy Chairman, Sir, I was forced to...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Look at the display board. Your Party's time was 17 minutes and that is over. Okay. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Mr. Patel, you are starting from zero and can go up to 17!

SHRI PRAFUL PATEL: Now, it is zero, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, this is his maiden speech! ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAFUL PATEL: Well, I will not take more time, Sir. There were a few things left. I was talking about the power sector when I was asked to sit down, and again assemble after lunch. Fortunately, Dr. Manmohan Singh, our former Prime Minister, is also here. The issue of coal shortages was mentioned by the Minister of Power. I think in today's newspaper and also in the last couple of days' newspapers, it has been coming that there is no coal. There is only two days coal availability. You should import coal to the State utility, NTPC. That is the way you can fulfil those shortages. Suddenly, there was a statement, again, which said, "No, no. We never said that there is any coal shortage." Whatever it may be, the fact is that to produce more power, more coal is required. The fact is that while you have very laudable targets of achieving higher energy production, there is no roadmap. I don't think a statement of intent is enough to suddenly change the power scenario or the entire sectoral outlook in this country. Gas prices, oil prices and petroleum product prices – your own Statements from the Government have emanated that, "We are deferring it by a few more months: we will take a decision." Probably, you have elections in Maharashtra and other States in mind; that is why, it is more of a political decision than a decision based on any fiscal prudence or discipline. Sir, I am just trying to recap because I have started again that while we talked of fiscal prudence and bringing the fiscal deficit down to 4.1 per cent, there is no sign at all in the entire Budget exercise which shows signs of an expansion of the economy, thereby the fiscal deficit can be contained. Until and unless you slash Plan expenditure and slash all other forms of expenditure and try to, in a way, contract the economy, you cannot achieve a fiscal deficit of 4.1 per cent. Many things have been mentioned. Again, in the morning, the

Road Minister was just trying to say that there were no takers for PPP projects in the road sector. So, what is the objective? How are you going to bring this entire exercise back on track and attract a higher level of investment? Since, Sharad Pawar*ji*, my Leader, has just come, I will, again, for refreshing the memory of the House and also of Javadekarji who was not here, say one thing which is very important. During the time of Dr. Manmohan Singh and Sharad Pawar*ji*, in the Ministry of Agriculture and at the Government of India level, special emphasis was laid on the agricultural sector. That is why we achieved the highest production of foodgrains in the country in the year 2013-14. It was the highest, that is, 269 million tonnes. The agricutlural credit was Rs.85,000/- crores in 2004, which was expanded to Rs.7,50,000/- crores in 2013 and which this year has been enhanced to Rs.8,00,000/- crores. It is a good thing and you continue to do so. But the fact is that in our country we have disproportionate number of peopie whose livelihood is based on agriculture as compared to the number of people in other developed economies, whose livelihood is dependent on goods, services and other sectors, rather than on agriculture. Therefore, in a rural economy like ours, we need to do that much more.

Sir, I would not like to repeat things, as I have said most of the things earlier, but one thing is clear, that on the housing sector, you have sought to lay a lot of emphasis. You have said that you would have a National Housing Bank, which would be given an initial corpus of Rs. 4,000 crores. Also, you have said a lot of things about the Urban Renewal Mission. But, talking of the concept of smart city', which I had mentioned earlier, I really fail to understand what the definition of a 'smart city5 is. Therefore, kindly explain that to us. I think, 'smart city' has become a buzz word, just like the talk of giving one AIIMS to this city, one IIT to that State, one smart city to Jammu, one to Kashmir, one to Telangana, and so on. A lot of people have been talking about smart cities. I think, the concept needs to be made very clear, rather than it being just another smart statement! So, that needs to be defined. (Time-bell rings) Why not have one smart city in the country as a model? You could have it for one or two years in Dholera, to begin with. In Dholera, land is already available; the airport was sanctioned by us; the port and everything else is there. Dholera could be one of the first smart cities. Let the Gujarat Model start from Dholera and be expanded to all parts of the country. I think that would be something very laudable.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, I am about to conclude. Since I was interrupted, my flow of thoughts really got pushed behind.

Then, Sir, it is good that you have opened up the defence sector for further Foreign Direct Investment. There may be many contrary views about this too. I think, we had

[Shri Praful Patel]

started this process during Dr. Manmohan Singh's time, by providing for 26 per cent FDI. Also, certain projects could have higher FDI, if it were to be approved by a certain committee at the highest level. You are expanding on that idea and, I think, that is a good thing. India needs it. For very small things we are dependent on import of defence equipment. In my opinion, those things are very, very easily available, or can be produced in our country. That would, boost manufacturing, create jobs, and would also reduce our dependence on imports. This is a laudable step and we should pursue this idea even more aggressively. It is important from a strategic point of view too. We could produce more and more in our defence sector, for home consumption as well as for exports, and do it indigenously.

Sir, on direct taxes, what you have done is a just a little bit of appeasement to our middle class. But, if we take into account the higher cost of living, inflation and high interest rates, I think, it really means nothing, in terms of the money that is left in the hands of an individual. Therefore, while on the one side, you have taken a lot of credit for having given something back to the middle class of our country, in an era of high interest rates and inflation, what you have given to them is actually a reduction from what could have come into their hands.

Then, Sir, I would like to say that for our energy sector, whether it is gas, oil or petroleum products, we need to really have a very aggressive roadmap. Seventy per cent-plus is imported even today. Over the years, a lot of investments have been made, both by the public sector and the private sector, but I do not think that India has yet been able to develop or exploit its fullest potential in the area of natural resources, petroleum and natural gas.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Praful*ji*, please conclude.

SHRI PRAFUL PATEL: Therefore, I think we need to take much more aggressive decisions on that front and bring in much more investments, because it just does not help the sector, with the kind of uncertainties involved in this sector. There are many projects which have been delayed. There are many power projects that are ready and up, but do not have the necessary gas or other fuel for running them. So, my suggestion is that we pursue the oil and gas sector in a much more aggressive way. Sir, I will end here. But I would say that in an overall context, the Budget has nothing new to offer. It has continuity but it does not have, I would say, anything radical as the Government has promised to give a dynamic change or a radical change for people of our country. We will wait for many years. We have decided to wait for five years. People have told us and we will wait for that. Nonetheless, I think, in certain areas of the economy like insurance, which

you have talked of, you would like to expand by bringing in more FDI. I think that is a welcome move. My party would not have any hesitation in supporting further opening up of insurance sector, the pensions fund, because these are ultimately the areas from where you will get the maximum money for our long-term infrastructure projects. With these words, Sir, I would only like to say a word of caution to the Government that while you have given us a Budget, you please give us a little bit more hope and a little bit more material and physical delivery of the laudable objectives with which you have given the Budget to the country.

SHRI K.T.S. TULSI (Nominated): Hon. Deputy Chairman, Sir, I am extremely grateful for giving me the opportunity and the honour of addressing this House and deliver the maiden speech. I consider myself extremely fortunate to be nominated by the President of India and I hope that I am able to maintain the high traditions of this august House and also serve as a worthy Member. I have great personal regard for the Leader of the House and we have been close friends at the Bar. In fact, in 1990 when I came here as the Additional Solicitor General, it was he who received me because it was his room which was allocated to me and I somehow managed to chase him into the Parliament. I would like to say that I am greatly mesmerized by his speech मैं उनके अंदाज़े बयां का कायल हूं और उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं वो यहां आए नहीं है, अभी लोक सभा में हैं,

"उनका अंदाज़े बयां रंग बदल देता है,
वरना दुनिया में कोई बात नयी बात नहीं।।"

मेरा इस सदन में सिंगल प्वाइंट एजेंडा होगा कि किसी तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पटरी पर लाया जाए। because criminal justice system, in particular, and the entire judicial system, in general, is drowning in the sea of delays. I am extremely concerned about the inadequate allocation of funds to the entire justice system. If there is rampant corruption in the country it is because we are unable to decide cases in five years, ten years or twenty years. I myself am handling cases where charges have not been framed for over ten years. This kind of a system can only lead to the complete collapse of values and the only ray of hope, to my mind, seems to be to modernize the police stations in the country. Every police station needs to be modernized. India is no longer a third-world country. We should have automatic recording of telephone lines of every police station in this country; we should have state-of-the-art interrogation rooms in every police station where the statements of witnesses are recorded with the aid of tamper-proof technology. Today, if the conviction rate is so abysmal, it is because the statements are written by semi-literate sub-inspectors and hardly carry any credibility in the courts. If there is such a low conviction rate, it is primarily because the witnesses

[Shri K.T.S. Tulsi]

find it very convenient to resile from the statements that have been recorded by the police. But if these very statements were recorded with the aid of tamper-proof technology, perhaps we would be able to push up the conviction rate because unless the conviction rate goes up, there is going to be no compliance of the laws.

We need to have a relook at the Whistle Blowers' Protection Act and unless this Act is extended to the private sector, it is going to be meaningless because most of the corruption is generated through the big business. We also need extensive witness protection programme. There is virtually no expenditure allocated for witness protection programme and honest witnesses are becoming harder to come by.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am greatly disappointed with the allocation of 0.4 per cent in the Budget for Law and Justice. The Hon. Finance Minister indicated in his speech that he wanted to establish more courts. How are you going to establish more courts with 0.4 per cent allocation? The total allocation for 2014-15 is ₹ 1,205 crore, which is significantly less than the allocation in the last year's Budget which was ₹ 1,973 crore. Where is the intent to implement the promise of more courts?

The Hon. Finance Minister in his earlier tenure as the Law Minister, was the author of a new innovative venture, that is the Fast Track Courts. There are over 1,000 Fast Track Courts in the country, but in ten years, they have disposed of 3.2 million cases, whereas the Judiciary is reeling under the burden of 32 million cases. In ten years, if all that the Fast Track Courts have been able to achieve is 3.2 million cases, it is extremely disappointing and there seems to be no ray of hope with the reduced allocation for Law and Justice. I want to say that this allocation includes the expenditure on 40-odd tribunals. And, what is the allocation provided for the tribunals? The Income-Tax Appellate Tribunal got Rs.4 crore last year, and this year, the allocation has been reduced. The National Tax Tribunal has been allocated a measly sum of Rs.5 lakh. The Appellate Tribunal for Foreign Exchange received Rs.8.25 crore, and this year, the allocation is Rs.25 lakh more than that of the last year.

Sir, I humbly submit that there is a serious problem with our Judiciary. There are 17,715 posts of Judges which is the sanctioned strength of Judges, in the country. There is something seriously wrong with the system of appointment of Judges because more than 3,300 posts are vacant. How can we have expeditious disposal of cases when there is so much gap between the Judges who are in position and the Judges who are sanctioned? Besides, there is a wide gap in the infrastructure that is provided to the justice system as compared to the other sectors. Sir, whether a nation is civilized, and, if yes, to what extent, is judged by the efficacy of the criminal justice system, and, it we are unable to decide the

guilt or innocence of persons for decades, I would submit that we cannot call ourselves a civilized nation. So, we have to pay attention and give higher priority to law and justice. Sir, criminal justice is paralyzed as a result of the gross neglect. The paralysis of criminal courts gives criminals a free hand. The law has lost its efficacy. There is no fear of law. It has become low risk-high profit business, and, that is why, the nation is reeking with corruption, scandals and general mayhem.

There are mounting arrears. The criminal cognizable cases to the tune of 1 crore 87 lakhs are pending in the country, and, 66 lakh of these cases were filed in 2013 alone. The trial in 2013 was completed in the case of about 47 lakh cases, which means that we are adding to the arrears every year. There is no hope of these arrears being removed unless we find some innovative solution. The mounting arrears have resulted in 95,000 cases of rape pending in the country; 1,70,000 cases of murder, serious crimes pending in the country; and, 4,00,000 cases are pending under Section 498A, that is, cruelty to women. Rising pendency has resulted, in both civil and criminal cases to the-tune of 3.2 crore.

I would like to mention to you the crime clock of our country. The crime clock is that one crime is committed against a woman every two minutes. Of course, it is a country with billion plus population but one crime against a woman is committed every two minutes. A case of molestation takes place every twelve minutes. A rape takes place every 22 minutes. Sir, no one can feign or fake a dowry death. A dowry death takes place every 61 minutes, and, every five minutes, there is a case of cruelty against women registered in some police station or the other in our country.

The saddest part of the story is that in our country the total strength of our prisons in the country is 3,20,000, and, gross abuse of human rights takes place because of overcrowding in our prisons, where we have to pack 3,69,000 prisoners in jails which are meant for far less a number of people. The worst is that 65 per cent of the prison population in the country is of under-trials, who are awaiting a decision about their guilt or innocence, and, many of them manage to completely serve out their sentence. They are so poor that they cannot afford bail. The monetary system in bails has to go because it operates against the poor. They cannot offer even one thousand rupees for a bail, and, they virtually serve out the sentence, and, then, there is no one left in the family.

I would like to submit that this state of affairs is resulting in two things. The conviction rate is steadily coming down and the crime rate is steadily going up. It is a recipe for disaster if we do not rectify the situation. I want to tell you that the conviction rate is determined by the National Crime Records Bureau on the basis of number of persons chargesheeted, and, therefore, they manage to show a higher rate of conviction.

[Shri K.T.S. Tulsi]

But if you take into account the persons arrested tor cognizable offences, and, the number of persons convicted, you will find that the conviction rate is far lower, perhaps as low as 6.4 percent. We find that in 2011, there were 3,613 cases which were registered while 5986 persons were chargesheeted. As against these, only 1,163 were convicted. Therefore, even with these statistics, there were only 19 per cent convictions, which means that all that you have to do if you are the accused is to delay the process. With the delay of the process, the witnesses get tired, and that is what results in such an abysmal conviction rate. The disposal rate by the courts is so poor and we keep on adding to the pendency. This is resulting in mob rule. I would only like to give you a few of the examples of the mob rule. In Bihar, a man was found beaten to death as he was suspected of theft of a bicycle. In Champaran, two kidnappers were lynched. The robbers are occasionally beaten to death. People have no patience with the courts now. If we do not speed up the criminal justice system, this is going to be a serious problem. What are the solutions? I submit firstly the wrong solutions which we have been following over the years. ...*(Time-bell rings)*... Five minutes, Sir.

The wrong solutions are more deterrent punishment. More deterrent the punishment, the lower the conviction rate. We have been putting restrictions on bail. That hardly serves any purpose. That only militates against liberty. Reversal of burden of proof goes against the Constitutional spirit. Some people say increase the number of judges. Mere increase in the number of judges is not going to help unless we improve infrastructure. It is said that we have 10.5 Judges per million and the world ratio is 50 Judges. If we compare the Judge-docket ratio, in the United States, a Judge disposes of 3,235 cases in a year, whereas an Indian Judge disposes of 987 cases. It is not that Indian Judges are any inferior. It is only because they lack the infrastructure. The infrastructure that is provided to them is only that of a bullock cart, hence that is the speed at which they will go. We need to modernize the police stations and we also need to modernize the criminal courts. All courts must have automatic recording facility of evidence. That is what will discipline the courts. The courts also must have simultaneous transcription. These are the facilities which are available world over. India is an IT super power. There is no reason why we cannot provide these facilities in our courts. Every police station needs to be provided with a mobile forensic van. It is a mobile forensic van which will go to the spot. One scientific evidence that is collected is equal to a hundred witnesses. Mobile forensic van must accompany the homicide team to the spot. Then, the conviction rate can significantly go up. I am extremely grateful for this opportunity. I do hope that one day we will be able to significantly improve our criminal justice system. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Tulsi*ji*. It was a very useful

speech for all of us. It was a very informative one also. ...*(Interruptions)*... Next in line is Shri Rajeev Chandrasekhar. But before I call him, I am calling Shri Sanjiv Kumar because he wants to catch a train. After him, I will call you.

SHRI SANJIV KUMAR (Jharkhand): As a representative of this House from Jharkhand, issues relating to forest and forest use are of deep concern and interest to me. Way back, in December 2013, I had raised the issue of how the *ad hoc* Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) was dealing with the issues relating to management of funds and the Parliamentary oversight in this regard. It has come to my notice that the CAG has tabled a Report on Compensatory Afforestation in India in Parliament in September 2013. It has dealt extensively with a number of issues relating to the regulatory failures in diversion of forest land, non/short recovery of over ₹ 5,000 crore of funds for compensatory afforestation and poor utilisation of funds released by *ad hoc* CAMPA to States.

Serious as the issues posed by the CAG in his Report may be, I, today, both as a parliamentarian and a member of legal fraternity, want to draw the attention of the Finance Minister and the Government to a far more serious and fundamental issue that the Report has flagged in the context of the debate on the General Budget for financial year 2014-15.

At the outset, I would like to quote from the Constitution of India. Article 114(3) of the Constitution enjoins "Subject to the provisions of articles 115 and 116, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of India except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article."

The Constitution is clear and unambiguous on the issue of authorisation of expenditure. All expenditure, including a single rupee has to be authorised by Parliament. Members will be surprised with what has been said by the CAG regarding the manner in which expenditure on compensatory afforestation is currently being incurred. I quote from para 6.3 of the Report of the CAG, Union Government No.21 of 2013.

"The institutional design for incurring expenditure from the CAF under *ad hoc* CAMPA and State CAMPA is somewhat distinct from the expenditure being incurred by both the Union Government and the State Government.

"In the case of expenditure being currently incurred by *ad hoc* CAMPA and by State CAMPA, there is no legislative authorisation for the incurrence of such expenditure. The money in the funds is kept out of Consolidated Fund of India based on the directions/ orders of the Supreme Court and the expenditure is incurred without authorisation from

[Shri Sanjeev Kumar]

Parliament. The Court passed its orders in 2002 when the quantum of expenditure was negligible during the initial years. Now by the end of March 2012, the expenditure incurred was Rs.1,775.84 crore against releases of Rs.2,829.21 crore. Given the large amounts being collected from user agencies under compensatory afforestation under the provisions of the Forest (Conservations) Act, 1980, and in the context of the objectives of CAMPA, it may be necessary to review the existing institutional design in consonance with the constitutional scheme with regard to the authorisation of incurring of expenditure on CAMPA related activities by approaching the Supreme Court, where considered necessary."

This fact of expenditure not being authorised by Parliament as per the scheme laid down in the Constitution would clearly have been known to the concerned Ministry which is the Ministry of Environment and Forests. The Finance Ministry after the submission of this Report of the CAG would also be aware of the fact of this serious constitutional breach.

Sir, I would like to know from the Government how and why the Appropriation Bill for financial year 2014-15 continues to exclude expenditure authorisation of thousands of crores of rupees relating to CAMPA.

श्री उपसभापति : आपके 5 मिनट पूरे हो गए हैं।

SHRI SANJIV KUMAR: Sir, do I have two more minutes?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

श्री संजीव कुमार : सर, आजादी के बाद 67 साल हो गए हैं, कहा जाता है कि झारखंड बहुत रिच स्टेट है। हम देश को टोटल कोयले का 32 प्रतिशत रि जर्व देते हैं, हम बॉक्साइट देते हैं, हम तांबा देते हैं, हम क्ले माइन्स देते हैं, लेकिन 67 साल की आजादी के बाद भी झारखंड राज्य का बजट कई बार आया, उसके बावजूद भी झारखंड की स्थिति ऐसी है कि अगर हम न्यूजपेपर में पढ़ते हैं कि किसी मेड या सर्वेंट के साथ अत्याचार हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में आता है कि वह झारखंड का है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है कि वह ट्राइबल है। इसलिए मेरा कहना है कि हम अपने यहां से जितना भी कोल या मिनरल्स देते हैं, उसके बाद वहां जो पॉल्यूशन होता है, उसके परिणामस्वरूप अस्थमा, टी.वी. और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो कोल और मिनरल्स के बदले हमें रॉयल्टी के नाम से जितना पैसा मिलता है, उसे हम उन बीमारियों के इलाज पर खर्च कर देते हैं। हाल ही में बहुत दिनों बाद सरकार ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि झारखंड में तीन मेडिकल कॉलेजेज खोले जाएंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ में यह भी उम्मीद जताता हूं कि कहीं यह भी विशेष राज्य के वायदे की तरह से वायदा बनकर न रह जाए।

मैं सरकार को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस चुनाव के समय बहुत बड़े-बड़े वायदे

किए गए थे, अच्छे दिन आने की बात झारखंड में भी कही गयी थी कि आपके अच्छे दिन आएंगे और हम आपके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि झारखंड के अच्छे दिन लाने का जो आपने वायदा किया है, उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के वायदे को जल्द पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Budget.

Sir, the Finance Ministers starts with an economy that has been left very weak and vulnerable by a scorched earth management of the economy — these are not my words, but that of a former Chief Economic Adviser — with 12 quarters of successive GDP declines and 24 quarters of successive inflation growth. Gross capital formation has declined in the last two years and for the first time in a few years, breaching 30 per cent, and an unprecedented trust deficit between the Government and investors, with investors having lost more than Rs.6,80,000 crore in PSU stocks alone over the last three years.

Sir, this Budget is really the first step in the difficult process of rebuilding the economy. It must be seen in that context. For most part of the last decade, the focus has been on growth through the consumption economy with investments being a lower priority. The evidence of this was very clear with projects and investments worth Rs.7,95,000 crore stuck in the pipeline. It is clear that investments were a secondary priority to the consumption economy. Sir, the Chief Economic Adviser last year mentioned in the .Economic Survey what many of us had been arguing for several years that the 2008 stimulus was flawed and aimed at the easy solution of consumption economy rather than the more difficult model of growth through investments.

So, Sir, in a nutshell, that's where we are today — at the bottom of a mountain that looks daunting, but that needs to be climbed and conquered. This Budget, to use a mountaineering metaphor, is like a base camp — low on theatrics and more about fundamental and structural issues of organizing and planning the real climb ahead. I have no hesitation in endorsing this Budget as a good solid first step.

Sir, let me congratulate the Finance Minister for saying in the other House that he is pro-business and pro-poor. There is no political and economic-contradiction in this and I hasten to-point this cut to my friends in the Left. This is really what this country needs — a steadfast commitment to investments and growth and a break from politicking of the poor and dividing the same small pie into thinner and thinner slices to make it go around; instead, a strategy of growing the size of the pie so that there are more slices and bigger slices to distribute to those who need help and support out of their deprivation and

[Shri Rajeev Chandrasekhar]

poverty. I congratulate him for saying that he does not believe in creating liabilities tor future generations. That is an important statement for the youth and future generations of the country.

Sir, I will speak about two specific issues. My colleagues have spoken at length about all the positives of the Budget. Sir, let me first bring the issue of public investments to the Finance Minister's attention. Sir, there is a total of 15 lakh crores of public money invested in 277 Central Public Sector Enterprises. For years, many of these PSUs have been mismanaged and the public equity invested in these has been put to losses. There is very little public discussion about the performance of the public's money that has been invested into these companies. For example, a company like BSNL which five years ago was valued at over Rs.50,000 crores has run into, losses. There must be some explanation and investigation as to what causes this. The Finance Minister needs to depart from the UPA's strategy of blindly investing more and more taxpayer and public money without fundamental restructuring of these companies and managements.

For too long, the cycle was one to put public money into PSEs, mismanage, loot and lose money, put more public money and this cycle of infamy will continue. I believe the Finance Minister as a principle must break this cycle once and for all.

Sir, the other area I want to talk about is PSBs - the public sector banks. My colleagues, Shri Naresh Agrawal and Shri Vijay Goel and others have referred to this issue. In recent times, the financial sector, and in particular, the Banking sector in India has begun to resemble something from Alice in Wonderland with the banks in particular looking like Piggy Banks for the rich and powerful. The sharp rise in NPAs and fall in their profitability has not been challenged or questioned enough. The NPAs have gone up alarmingly in the last 2-3 years and there is a direct-loss in value-of public equity and tax payers money in these Banks. The Finance Minister has mentioned re-capitalisating the PSBs with Rs.2.4 lakh crores is a significant investment of public money. This capitalisation must be accompanied with significant restructuring and reorganising of these banks especially how they are managed, especially in areas of risk and credit assessment. I accept in some cases, PSBs are now holding the can for flawed Government sectoral policies because they are directed to land in the name of infrastructure development and then coerce to give the go-by to normal prudent lending norms. This creates two serious issues that the House must debate. I hope the Finance Minister will look into it.

Firstly, and at a time when we need to create hundreds and thousands of new entrepreneurs, the industrial groups are cornering all the capital and opportunities.

Second, the phenomenon of big businessmen glibly escaping the responsibility of

repaying personally guaranteed loans while banks pounce on small and middle income families and SMEs who default their home, car, 2 wheeler, farming, education loans and other loans exposes the double standards in the public sector banking. This is neither tenable nor acceptable, and-constitutes a severehazard of the worst kind, made even worse when some of these businessmen are in positions in Parliament. The public sector banking system needs reforms, and I hope the Finance Minister would address this issue before pumping further capital and public money into it.

Sir, let me come to the issue of private capital and PPPs. Sir, I believe that private capital has a big role to play in the growth of our economy and country. Here is another area were the Finance Minister needs to make some significant changes from the UPA. Most of the PPPs seem to be one sided deals that have resulted in windfall gains to the private sector. The CAG Reports on PPPs in Petroleum, Gas, Airports, Railways and Telecom have all raised serious questions of transparency, fairness, propriety and in several cases questions of outright manipulation and corruption. Just a reading of one of these reports is enough to make you wonder about people getting away with brazen violations at the cost of the Government and taxpayer and creating a culture of crony capitalism that has been much written and spoken about in this House.

Sir, I will take just a few moments. There are two important effects of this kind of PPP approach-one is that public and Government side of the PPP always loses, and there is a real risk that public opinion will start opposing PPPs and the other is that genuine investors will stay away, give the taint and lack of transparency of doing business through PPPs in India. Sir, my suggestion to the Finance Minister would be to focus on making projects investment grade, where equity and debt flow into these projects naturally because of their viability and risk mitigated nature, and not by directing PSBs to lend. Because directed lending may create an asset in the short term, but it will only create a problem for the banking sector in the future. The Finance Minister must remember that he is a joint custodian of the economy and the sole custodian of the financial sector. The Chinese wall between these, to use an unfortunate phrase, needs to be respected, if you are not to damage the banking system, as was done all these years.

Sir, I quote from the BJP Manifesto, "PPPs should be encouraged. An institutional network will be established, while regulators will be given autonomy and accountability." The Finance Minister is already aware of my strong views on the need to create independent regulatory institutions to make investors confident of investing in long-term projects, and so I will not say anything more about this.

Let me end, Sir, by saying, a joke in India now is, if you have a business and you

[Shri Rajeev Chandrasekhar]

want to make money पैसा बनाना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लो और वापस मत दो, या फिर गवर्नमेंट के साथ पी.पी.पी. करो। This is the recipe for business success in India. That must change.

Entrepreneurship and wealth creation is important for our economy, but the policies must be reoriented to ensure that success is a result of hard work, innovation and creativity, rather than contacts and connections in Delhi.

Let me end with a message for the Finance Minister by modifying a Bill Clinton quote, "No generation has had the opportunity that you have to build an economy that leaves no one behind. It is a wonderful opportunity, but also a profound responsibility." I wish him all the best. Thank you. Jai Hind.

DR. KARAN SINGH (NCT of Delhi): Mr. Deputy Chairman, Sir, my colleague, Shri Anand Sharma, has already made an incisive speech on the Budget as have other Members of the House. I rise simply to bring to the notice of the Government and the House two specific matters flowing from the Finance Minister's Speech. The first is the whole question of linking of rivers. It sounds very impressive. I remember the idea was mooted 60 years ago by Dr. K.L. Rao, who was in the Council of Ministers of Pt. Jawaharlal Nehru. But, now it seems that the Government is seriously considering this. Environmentalists, hydrologists and economists around the world have expressed deep concern at the irreversible damage that this sort of a mega project can do to the country's environment and to the whole hydrological picture underground and above ground of our water resources. Massive civil works will be involved; lakhs of people will be uprooted; vast sums of money will be required; settlement of uprooting people will be required. Even in the case of the dams that we made in the early years of Independence, the Bhakara Dam and the Pong Dam, people have still not been fully rehabilitated. Can you imagine how many lakhs of people will be displaced as a result of this sort of project? So, I just want to read one paragraph from a water expert scientist. He says, "Rivers have an ecological identity of their own regardless of the human stakeholder interest. The river, its catchment and basin is a water course made by nature over evolutionary time of tens of millions of years, which once damaged cannot be reclaimed. Human intervention is never foolproof. Tampering with nature has always resulted in unforeseen injury and adversity for rivers. The backbone of a river water policy must highlight the non-invasive use of rivers which will be irrevocably and irreversibly injured if we go in for the interlinking." Sir, I must urge the Government to try and look for alternative methodologies, the better use of existing rivers, preventing grim pollution, such as the Ganga, the Yamuna, water harvesting and so on. But please be aware that these massive sorts of Stalinist and Maoist type of projects are no longer now acceptable to the forward-thinking people.

3.00 P.M.

What is needed now are much more carefully thought out, much more carefully prepared, projects which can deal with individual rivers but not with the huge idea of linking one river in the North all the way to the South thereby destroying, on the way, unlimited amount of land and population. So, please proceed on this with caution. I am raising a note of caution on river valley because the river water is, specifically, mentioned in the Finance Minister's speech.

Sir, the second point which I am raising is the question, of population stabilization. Apparently, this has fallen off our radar and totally ignored in the President's Address and in the Finance Minister's speech. Our annual exponential growth is still 1.63 per cent which works out to 2 crores of people every year. That is the population of one Australia. Sir, when we are adding one Australia every year to the population of India, how much pressure it is putting on our resources! Our *kisans* are doing a fabulous job but there is also a limit to the amount they can do. Be it our water resources, food resources, educational resources or employment resources, there is a limit to everything. It is quite astounding that we have not been able to bring down the rate further.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no effort in that direction.

DR. KARAN SINGH: That is what I am saying. There is no effort whatsoever in that direction. None of the five paragraphs of the Finance Minister's speech on Health and Family Welfare mention population strategy. It has become a radioactive word and, I am afraid, we have got to rethink on this. I remember, I led the Indian Delegation to the First World Conference on Human Population in Bucharest in the early 70s. What do we need now? We need a clear-cut Population Policy. I presented the first Policy to Parliament in 1976. It has been revised many times over. We need a massive Public Educational Programme for our institutions. We need a massive Condom Distribution Programme without which you cannot control this problem, and that will also help in fighting the dreaded disease of HIV. And we need to use the latest contraceptive technology. Women need to be empowered. As long as the women of India are not empowered, this family problem will never be solved. So, they must have access to contraceptive technology. They must be able to say how many children they want to have. They cannot just become children-bearing machines without their will. So, Sir, it needs a new mindset. It needs an entirely new philosophy. And this must cut across party or religious or caste or any other line. There has to be a commitment, a national commitment to population stabilization. That is my sincere hope, and this is my advice to the Finance Minister and my submission to the whole House. Thank you, Sir.

श्री विजय गोयल (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जनरल बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। पहले जब बजट आता था, तो लोग सोचते थे कि बजट के अंदर ही महंगाई बढ़ेगी या कुछ वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारा साल, बीच-बीच में कुछ न कुछ महंगाई बढ़ती रहती है या दूसरे टैक्स वगैरह लगते रहते हैं। पहले लोग कल्पना करते थे कि हम टेलीविजन या कार पहले खरीद लें, कहीं बजट के अंदर इनके दाम बढ़ न जाएं।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री तिरूची शिवा**) पीठासीन हुए]

किन्तु अभी मेरा यह कहना है कि हम लोगों की कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम खाद्यान्न में, शिक्षा में, दवाई में, परिवहन में बीच-बीच में दाम न बढ़े, बल्कि एक साल के बाद ही इस तरह से बजट आए, जिससे लोगों को लगे कि अब इसके बाद महंगाई या टैक्स बढ़ने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनन्द शर्मा जी ने अपनी बहुत सी मजबूरियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल फिनॉमिना था, वर्ल्डवाइड फिनॉमिना था, ग्लोबल हेडविंड्स थे, जिनके कारण इस सरकार की मजबूरियां थीं कि अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पायी। मैं कहता हूं कि सरकार व्यापारी की तरह चलनी चाहिए। जिस तरह से एक व्यापारी अच्छी प्लानिंग करता है, जब सर्दियां आती हैं, तो हमें लगता है कि कंबल चाहिए, हीटर चाहिए, गर्मियां आती हैं, तो लगता है कि कूलर या कोई और वस्तु चाहिए, तब ये सब चीजें उसके पास मिलती हैं। हमें मालूम होता है कि हमें वह सब उसकी दुकान में जरूर मिलेगा। वह सब चीजों की प्लानिंग करता है। उसी तरह से सरकार को भी पहले से ही सारी प्लानिंग करके चलना चाहिए था। एन.डी.ए. की सरकार में जिसने सबसे ज्यादा संकट देखे थे, मुझे उन वाजपेयी जी की याद आती है। 1998 में परमाणु विस्फोट हुआ, सब तरह के सैंक्शन्स लग गए, बड़े-बड़े देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शन्स लगाए, पर वाजपेयी जी देश की इकोनॉमी को निकाल कर ले गए। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करना चाहता हूं। 1999 में कारगिल युद्ध आ गया। हमने कारगिल युद्ध जीता और अर्थव्यवस्था को भी कायम रखा। 2001 से 2003 तक पूरे देश के अंदर सूखा पड़ गया, पर हमने उस सूखे का सामना किया। उसका सामना करने के बाद हमारी इकोनमी ठीक चलती रही और हमने महंगाई भी नहीं बढ़ने दी। 2004 में बिहार और दूसरे प्रदेशों में बाढ़ आ गई, किन्तु हमने उस बाढ़ का भी सामना किया। वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार देश की अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से निकालकर ले गई और महंगाई भी नहीं बढ़ने दी।

उपसभाध्यक्ष जी, यदि आपको ध्यान हो तो उनके राज में एन.डी.ए. सरकार के अंतर्गत, जब कोई एक सिलेंडर लेने जाता था, तो उससे कहते थे कि आप दो सिलेंडर ले लीजिए, किन्तु अब ऐसा नहीं है। अभी जो सरकार आई है, उसको विरासत में बीमार अर्थव्यवस्था मिली है, उसका सबसे बड़ा कारण लोग जो गिनाते हैं, वह यह है कि उनके पास गठबंधन की मजबूरियां थीं, उस पर गठबंधन के प्रेशर्स थे, इसलिए टू.जी. जैसे स्कैम्स हो गए। उसमें भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, अर्थव्यवस्था चौपट थी और पॉलिसी पैरालिसिस था। उसके लिए कहा जाता था कि प्रधान मंत्री फैसले नहीं ले सकते हैं। उसका पावर सेंटर एक नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... पहले की भी सरकारें अपना अच्छा बजट लाती होंगी, किन्तु दोनों सरकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह सरकार इस बजट को

इम्प्लिमेंट करके दिखाएगी। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत पुराने टाइम से जानता हूं। मैंने वित्त मंत्री जी के साथ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई की थी। मैंने उनके साथ लॉ भी किया था। जब वे यूनियन में प्रेसिडेंट थे, तब मैं सेक्रेट्री था, इसलिए मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी जिस काम को ठान लेते हैं, उसको पूरा करके दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि इस बजट के अंदर उन्होंने जो विज़न रखा है, हमारी सरकार उसको पूरा करके दिखाएगी।

हमारी एन.डी.ए. और यू.पी.ए. की सरकार में इतना फर्क है कि हमारे पास वे मजबूरियां नहीं हैं। हमारी सरकार अपने own पर है, हमारी सरकार गठबंधन की सरकार नहीं है। हमारे जो एलायज हैं, वे हमारे साथ हैं। वे हमारी मजबूरियां नहीं हैं, इसलिए हम कड़े फैसले ले सकते हैं। हम संविधान में परिवर्तन करके नई नीतियां ला सकते हैं। हमारी सरकार बहुमत से जीतकर आई है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस सरकार में कठिन निर्णय लेने की क्षमता है। हमारी सरकार को टू जी, कोयला ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे करोड़ों रुपये के भ्रष्टचार का सामना नहीं करना है।

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu) : What type of changes do you bring in the Constitution?

SHRI VIJAY GOEL : I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) : He is not yielding.

श्री विजय गोयल : जब मैं कांस्टीट्यूशन की बात करता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि हमें संविधान में किन्हीं नीतियों के अंतर्गत परि वर्तन लाने की जरूरत होगी, तो इस सरकार में वह ताकत है कि परि वर्तन कर सके। हमारी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं है। हमारे पास एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है और हम ''सबका साथ-सबका विकास'' की नीति लेकर चल रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनसे रेग्युलरली मिलता था, ये सभी सजेशन्स भी लेते थे, पर इम्प्लिमेंट कितना करते थे, इसको मैं नहीं बताऊंगा, यह आपको संजय बारू जी की किताब में पढ़ने को मिलेगा। कल आनन्द शर्मा जी ने भाषण दिया था। उनको भाषण देते समय देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ रिचुअल कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि सरकार का यह बजट बहुत अच्छा है। एक बात और है, जो मुझे समझ नहीं आती है, जिसके बारे में मैं कंफ्यूज हूं। आनन्द शर्मा जी कहते हैं यह बजट अनइंस्पायरिंग है, no big picture, no vision, मनमोहन सिंह जी कहते हैं इसमे लक्ष्य हासिल करने का रोड मैप नहीं है, शरद यादव जी कहते हैं यह शब्दों का गुलदस्ता है और बजट के साथ बुरे दिनों की शुरूआत हुई है। अलग-अलग लोगों ने बजट के बारे में अलग-अलग बोला है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले यू.पी.ए. इसका फैसला कर ले, क्योंकि बीच-बीच में यह भी कहा जाता है कि यह सरकार हमारा बजट, हमारी नीतियां लेकर आ गई है। आप पहले यह फैसला कीजिए कि यह बुरा बजट है या आपकी यू.पी.ए. सरकार का बजट है, उसके बाद तय होगा कि यह कैसा बजट है। कल नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि जब टिटहरी चिड़िया दोनों पैरों को ऊपर करती है, तो उसको लगता

[श्री विजय गोयल]

है कि जैसे सारा आकाश उसने संभाल रखा है। आप टिटहरी चिड़िया की बात क्यों करते हैं, आप कृष्ण की बात करिए, जिसने गोवर्धन को संभाल रखा था और उसके नीचे वे जनता की सारी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार बैठे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गोवर्धन को कृष्ण की तरह उठाएंगे और इस देश की समस्याओं को हल करके दिखाएंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, कल नरेश अग्रवाल जी ने एक शेर पढ़ दिया कि "अब तो अच्छे दिनों से डर लगता है।" मैं उनसे कहना चाहता हूं-

"हमारे बारे में कोई राय कायम न कर दोस्त,
यह बदलेगा तो तेरी राय भी बदल जाएगी।"

मुझे मालूम है कि जिस समय सरकार के 5 साल पूरे होंगे, आप ही लोग खड़े होकर इस बात को कहेंगे कि हां, एन.डी.ए. की सरकार ने जो कहा था, उसको करके दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने एक सपना देखा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अन्दर अगर कोई मोची है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई बिजनेसमैन है, तो उन सबको अपना काम करते हुए यह लगना चाहिए कि मैं अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं देश का काम कर रहा हूं, मैं देश का विकास कर रहा हूं। जब हम लोगों के बीच यह स्पिरिट आएगी, तो मैं यह समझता हूं कि उन्होंने जो सपना देखा है यह जो बजट आया है, पूरा देश उसको पूरा करने में लगेगा।

हमने जो अर्थव्यवस्था सौंपी थी, उसमें जी.डी.पी. की विकास दर 8.4 परसेंट से अधिक थी, इंफ्लेशन रेट 5 परसेंट से कम था, फिस्कल डेफिसिट को हम 6 परसेंट से 4.3 परसेंट तक ले ही आए थे, करेंट एकाउंट सरप्लस 7.3 अरब डॉलर का था और औद्योगिक विकास दर 7.3 परसेंट थी, पर हमें जो बीमार अर्थव्यवस्था मिली, उसमें जी.डी.पी. की विकास दर 5 परसेंट से चीचे थी, मंहगाई दर 9 परसेंट से अधिक थी फिस्कल डेफिसिट 4.5 परसेंट और औद्योगिक विकास दर एक परसेंट से भी नीचे पहुंच गई थी। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हमको तो दो हफ्ते में लोग कहने लग गए कि आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ गए है। आप हमें दो हफ्ते नहीं, दो महीने नहीं, कम-से-कम दस महीने दीजिए, हमने आपको दस साल दिए थे, हम आपको करके दिखाएंगे और इस महंगाई को भी नीचे लाएंगे। आज प्याज के दाम बढ़ नहीं पाए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : इसका मतलब यह है कि दस महीने तक दाम नहीं घटेंगे, यह आपने कह दिया। सरकार की तरफ से जनता को यह संदेश दे दिया गया है कि यह मान लीजिए कि दस महीने तक दाम नहीं घटेंगे।

श्री विजय गोयल : राजीव जी, जो अर्थव्यवस्था हमें मिली है, उसको ठीक करने में जितना समय लगेगा, उतना समय तो हमें चाहिए।

श्री राजीव शुक्ल : टमाटर तो अभी उगा है।

श्री विजय गोयल : टमाटर भी आपके कारण महंगा हुआ, वह लाल भी आपके कारण हो रहा है, आपकी नीतियों के कारण हो रहा है। हमारी उपज तो अभी आएगी। किसी ने आपके बारे में कहा है-

"तुमने हालात इतने बिगाड़े हैं इस जमाने में
वक्त तो लगेगा ही उनको अपनी जगह आने में।"

इसलिए थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा।...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल : विजय जी, आप मेरा भी एक काउंटर शेर सुन लीजिए-

"शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है,
जिस शाख पर बैठे हैं, वह टूट भी सकती है।"

श्री विजय गोयल : आप मेरा भी एक शेर सुन लीजिए

"तू इधर-उधर की बात न कर,
ये बता कारवां लुटा क्यों था?"

इतने सालों के अन्दर अर्थव्यवस्था लुट गई, उसके बारे में राजीव शुक्ल जी, आप क्या कहेंगे? यह जो आपकी सरकार गई, यह अर्थव्यवस्था चौपट होने के कारण गई। ...(**व्यवधान**)... यह जो आपकी सरकार गई, यह महंगाई के कारण गई। ...(**व्यवधान**)... यह जो आपकी सरकार गई, यह भ्रष्टाचार के कारण गई। यह मैं बताना चाहता हूं।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : मेरा भी एक शेर सुन लीजिए-

"शोहरत की फिज़ाओं में इतना न उड़ो सागर,
परवाज़, न खो जाए इन ऊंची उड़ानों में।"

†[چودھری منور سلیم : میرا بھی ایک شعر سن لیجئے۔

شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساگر
پرواز نہ کھوجائے ان اونچی اڑانوں میں]

श्री विजय गोयल : आप शेरो-शायरी पर मत जाना, मैं चांदनी चौक से हूं, मैं गंगा-जमुनी तहजीब को जानता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) : Kindly address the Chair ...*(Interruptions)*... Don't exchange your words. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल : सर, मैं तो सिर्फ उनको बता रहा था। मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार में फर्क है। पहले जब प्याज सौ रुपए किलो हो जाता था, तब जाकर सरकार जागती थी,

---

†Transliteration in Urdu Script.

[श्री विजय गोयल]

लेकिन इस सरकार ने पहले दिन से कदम उठाने शुरू किए, चाहे वह निर्यात के मामले में हो, हमने उसका रेट सीधा 500 डॉलर किया, चाहे जमाखारों के ऊपर छापे मारने के मामले में हो, हमने तो इनके जमाने में जमाखोरों के ऊपर छापे लगते आज तक नहीं देखे, चाहे फूड सिक्योरिटी स्कीम की मीटिंग हो या खाद्य मंत्रियों की मीटिंग हो, हमने लगातार इसके ऊपर काम किया। लेकिन इस सरकार को अभी समय लगेगा। महोदय, मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं और न ही हमारे प्रधान मंत्री जी यह दावा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की तरह उन्होंने यह वायदा कभी नहीं किया कि मैं सौ दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप हमें 60 महीने के लिए चुनकर लाए हैं, इसलिए चीजों को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। मेरा कहना यह है कि दोनों सरकारों में आपको फर्क सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं, यह जो बजट है, विलपावर और विज़न वाला बजट है। मोदी जी सपने देखते हैं, तो उनको पूरा भी करते हैं। यह मोदीनॉमिक्स है, इसलिए यह सरकार भिन्न होगी। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण व बजट के अन्दर तालमेल है। आनन्द शर्मा जी ने खुद यह कहा था कि इसके अन्दर खर्च और आमदनी में तालमेल है। यह संतुलित बजट है, जिसके अन्दर पूरे देश के बारे में सोचा गया है।

अगर मैं लम्बी लिस्ट पढ़ने लगूंगा, तो बहुत समय लगेगा, किन्तु जिस देश के अन्दर 80 फीसदी से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, उस देश की ग्रामीण सड़कों के ऊपर 14,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मनरेगा जैसी स्कीम, जो आधी से ज्यादा भ्रष्टाचार के अन्दर चली गई, उस मनरेगा स्कीम को भ्रष्टाचार मुक्त करके ग्रामीण विकास के साथ जोड़ने का संकल्प इसी सरकार ने लिया है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' बनाया गया है। मैं सिर्फ गांव, ग्रामीण और गरीब के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। ग्रामीण आवास के लिए ऋण दिया गया है। 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कृषि के लिए दिए गए हैं। किसान टी.वी. शुरू किया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री अब यह सपना भी देखते हैं कि मिट्टी के अन्दर कौन सा उर्वरक, कौन सा कैमिकल और कौन सा फर्टिलाइजर डाला जाए, इसके लिए सॉइल टेस्टिंग के सिस्टम बनाए जाएं। किसानों का टी.वी. शुरू करके, उनको कृषि के बारे में ज्यादा एजुकेट किया जाए।

इस देश के अन्दर सिंचाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपया रखा गया है। 'सभी के लिए आवास योजना' रखी गई है। 'दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना' के माध्यम से हम पूरे देश के अन्दर बिजली देने का सपना देख रहे हैं। हम एक-साथ पूरे देश में बिजली की कल्पना करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह से पावर जनरेशन हो सकता है।

हमारी सरकार ने ''बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ'' का अभियान शुरू किया है। 100 स्मार्ट शहरों के ऊपर बहुत शोर हो रहा है। हमनें 100 स्मार्ट शहरों की बात कही है, हमने यह कभी नहीं कहा कि पूरे के पूरे सब नये शहर खड़े हो जाएंगे। कुछ शहर नये होंगे और कुछ के अन्दर अत्याधुनिक सेवाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाएगा। आप लोगों को इसकी तारीफ करनी चाहिए।

हमने एफ.डी.आई. के अन्दर बीमा और डिफेंस के अन्दर एफ.डी.आई. की बात की है,

ताकि जितने भी रक्षा उत्पाद हैं, वे हमारे अपने देश में ही बन सकें। अनुसूचित जाति योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 38,000 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया है। चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, उनके लिए मदरसों की आधुनिक ढंग की व्यवस्था की गई है। मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकार ने किसी भी तरह से इस पर काम किया था।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी को अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूं और चाहता हूं कि उन सुझावों पर वे अमल करें।

मेरा सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इस देश की इकोनॉमी टूरिज्म से चल सकती है। जहां तक मेरी नॉलेज है, इसके लिए 500 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो काफी नहीं है। चूंकि मैं चांदनी चौक, दिल्ली से आता हूं। मैं चाहता हूं कि चांदनी चौक को वर्ल्ड हेरिटेज सिटि डिक्लेयर किया जाना चाहिए, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश के अन्दर 5000 से ज्यादा तो ए.एस.आई. के स्मारक हैं, इसलिए इस देश में टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल उपलब्ध है। आज टूरिज्म एक जनरल टूरिज्म नहीं रह गया है, उसके अन्दर मेडिकल टूरिज्म आता है, उसके अन्दर रिलीजियस टूरिज्म आता है, उसके अन्दर एजुकेशनल टूरिज्म भी आता है। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं, जो टूरिज्म की इकोनॉमी के ऊपर ही चलते हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि टूरिज्म को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं राजस्थान से एम.पी. हूं, यहां जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर जैसी सिटीज़ हैं। राजस्थान वीरों की धरती है। ...(**समय की घंटी**)... मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। राजस्थान में 2,47,000 किलोमीटर रेगिस्तानी एरिया है। हम चाहते हैं कि उसका यूटिलाइज़ेशन एस.ई.जेड. लाकर होना चाहिए। मैं राजस्थान के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करता हूं। वहां सूखे और रेगिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको देखते हुए सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

THE VICE -CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) : Thank you, thank you.

श्री विजय गोयल : सर, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। मैं चाहता हूं कि सरकार वायदा बाजार पर भी अंकुश लगाए, चाहे वह उसको बैन करे चाहे उसके लिए कोई रूल्स-रेगुलेशंस बनाए।

दिल्ली इस देश की राजधानी है, लेकिन 15 साल के अन्दर कांग्रेस ने उसको स्लम बनाकर छोड़ दिया है। ...(**व्यवधान**)... किसी दिन मेरे साथ दिल्ली देखने के लिए चलिए। 60 लाख लोग अनधिकृत कालोनियों में रहते हैं, 40 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों के अन्दर रहते हैं, 30 लाख लोग स्लम्स के अन्दर रहते हैं। इसलिए इसको ठीक करना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) : आप यह देखिए कि चांदनी चौक का क्या हाल है? ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल : मैं आपकी तरफ से सरकार से कह ही रहा हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है और आप सब लोग यहां रहते हैं, इसलिए दिल्ली को ...(**व्यवधान**)... Sir, I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) : Please don't exchange words liks this. Address the Chair, please.

श्री विजय गोयल : सर, मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लिए भी सरकार को एक बजट रखना चाहिए। उसके लिए एन.सी.आर. का विकास करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या के नियंत्रण पर भी सरकार को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि भारत की संस्कृति के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि:

"हम सूरज होने का दावा नहीं करते
और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से।
किन्तु हम दीया जरूर हैं,
तम से युद्ध करना एकमात्र हमारा लक्ष्य है।
हवाएं दुखों की और अंधड़ तकलीफों की,
हमारी लौ को डिगा तो सकती हैं,
लेकिन बुझा नहीं सकती।"

जय हिन्द, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you, Mr. Goel. Now, Ms. Anu Aga. This is your maiden speech. You can take 15 minutes.

MS. ANU AGA (Nominated): Sir, I have been a Member of the Rajya Sabha since May, 2012, and I am really happy to be able to make my maiden speech today. The Budget has given me the opportunity. While all of us are proud of some of the achievements of our nation, we have our individual concerns. For me, of the two most critical social issues facing India, first is, malnourishment. Though, malnourishment is critical, I would like to focus on the second issue of quality education, especially at the primary level. As mentioned in the Budget, India has fallen from 134 to 138, out of 186 countries, in the human development index ranking for 2012-13. I have seen with my own eyes what the power of education can do to transform the life of a human being. Let me give an example. Dr. Mashelkar, who was the head of the Council of Scientific and Industrial Research, came from an economically disadvantaged background. His father had died when he was six. But fortunately for him, his almost illiterate mother pushed him to continue his studies. He went to a municipal school in Mumbai and eventually went on to finish his Ph D. We know the rest of the story. The sad reality is that 65 per cent of our children do not finish higher secondary school, and only about 12 per cent go on to

higher education, which means that 90 per cent of our children are unable to realize their true potential. How many of these children could become the next Dr. Mashelkar or Dr. Ambedkar, the guiding spirit behind our Constitution and who rose to such eminence through the power of education.

Sir, I have been involved with education for 18 years, and am associated with two NGOs which are promoting education for the under-privileged children. As you know, today, there is a great divide between municipal and the high-end private schools, and the quality of education in most municipal schools is deteriorating. This is in spite of the combined Central and State spending on elementary education. It has increased by 138 per cent from 2006-07 to 2011-12. In the same period, Government expenditure per child in public schools has increased by 120 per cent. And, yet, I repeat, quality keeps going down leading to growing number of households who chose to exit the public school system. Wealth and privilege often determine the choice of schools for our children. Thus, the social divide of our school system, private *vs.* municipal, often reinforces social division.

We know for sure that when we educate a child well, we improve her ability to make choices and lead a healthy and productive life. And, so, in the myriad challenges that our nation faces, I believe that a strong focus on giving every child, and, I repeat, every child, a good education will be the single-most effective lever in bringing about a wide-range of change towards an India that we wish to create, an India that lives up to our constitutional promise. Even if we discount the results of the controversial Programme for International Student Assessment, PISA, we need to take heed of the 2012 and a new Annual State of Education Report, ASER, an Indian survey conducted by Pratham every year. It has brought out that the quality of education in municipal schools is deteriorating especially in languages, mathematics and science. As parliamentarians, I am sure we are alarmed and concerned about the results from the surveys and would want to do something about the quality of our school education.

One important factor in a child's life is the teacher. By and large, the quality of teachers coming out of our current teacher training institutes is substandard. Unless we radically improve the quality of our teacher training institutes, we will not be able to change the education landscape. I welcome the new initiative called Pt. Madan Mohan Malaviya New Teacher Training Programme to infuse new training tools and motivate teachers with an initial sum of Rs.500 crores. This is much needed but we also need to audit the capability of all our teacher training institutes. Unfortunately, being a teacher is not an aspirational profession in India. If a surgeon does not do his job well, the word will go around and patients will quickly stop coming. The same is for a lawyer or any

[Ms. Anu Aga]

other profession. But if a teacher spends all his or her life without impacting the students, nobody stops them from being teachers. Where we need the highest quality and the greatest accountability, we are willing to live with mediocrity. It is time we imagine and create an India where teaching is aspirational, the profession attracts the best talent, is respected and our teachers meet the highest expectations. The Right to Education Act has ensured that almost all children between the age of 6 and 14 are enrolled in school. However, it has not ensured retention, because RTE focuses mainly only on inputs and not on outcomes. For example, RTE demands that every teacher must have a B.Ed, or D.Ed, qualification before entering the school system but there is no mention of the quality of education that these teachers impart. A degree in itself does not make a good teacher. Most of our teachers in our system lack the skill and enthusiasm. I have seen many non-B.Ed teachers do a better job, thanks to their passion and commitment, than the ones with B.Ed. A recent Teacher Eligibility Test, TET, taken by qualified teachers showed that less than 10 per cent of the graduates were fit to teach and these results were after special coaching to teachers. We, therefore, need to transform the teacher training institutes and introduce innovative teaching methods, so that we consistently produce good teachers. We also need alternative routes to teacher certification to bring more competent people into education and keep the bar very high. Luckily, in our country, the thirst among parents to educate their children in a good school is tremendous. The result is that many affordable private schools have mushroomed. These schools certainly are not great, but many of them do better than the Government schools. This is why so many economically poor parents spend their scarce resources educating their children in these schools, rather than choosing municipal schools where education is free. The well-to-do, in India, are for 100 per cent privatization of education because the public system, as it is today, does not deliver. There is corruption, mismanagement and complete disregard for human dignity. However, in the long run, unless we revamp the public system and offer quality education, it will lead to growing inequity. But, till we bring quality education, we should not close down private affordable schools, as stipulated in the RTE. Using the same yardstick, have we closed any municipal schools?

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Let me turn to my friends and ask as to how many of us send our children to a Government school. My hunch is, not a single one of us. If the rich are given the choice, why take it away from the poor?

Now, I would like to talk a little bit about secondary education. Time and again, surveys and media reports show that the poor are acutely aware of the need of their children to pursue secondary education. The reality is that, as a nation, we have failed to

create opportunities for poor children to study beyond the primary level. Let me illustrate this by giving an example from my own city of Pune. There are 307 municipal primary schools and only 23 secondary. The enrolment in the urban areas, in secondary schools, is low because parents are keen that their children learn in English medium schools. The second reason is that the standard of education is worse than in primary schools, since secondary schools lack subject-specific teachers. In rural areas, the problem is of access to secondary schools. Our nation does not have clearly-articulated national standards of achievement of our children; assessments aligned to these standards; resources for our teachers and our students, based on these standards. Developing these would allow every teacher to know the standards and learning outcomes for each grade and provide a roadmap for reaching there. Our society is still grappling with the question of how to truly promote inclusion and diversity. With an estimated 10 per cent of our children with special needs, our schools must prioritize on supporting them. We must remember that when we make a classroom work for the most vulnerable child, we make it better for every child.

Across the nation, there has been an uproar from some of the private schools against the idea of having 25 per cent kids from marginalized backgrounds, as required by the RTE. I understand the social and financial challenges. But I also know that it is our moral imperative to make this work–not just for the 25 per cent children who we bring in, but for the other 75 per cent also. In our society, inclusion and diversity will be valued when our children grow up together — supporting each other, playing together, sharing the beauty of their diverse backgrounds. And, what is inspiring is, it does work. In Kolkata, a missionary school Principal, Sister Cyril, integrated 300 girls, living on the streets, into her high-income convent school. This was done way before the RTE made it compulsory. When asked whether the parents objected, she said, of course, they did. But she promptly responded, "Do I seek their permission to teach maths? Do I seek their permission to teach science? But you are asking me to seek the parents' permission to teach compassion?" Let us look at the 25 per cent clause as the greatest gift we can give our children — the gift of learning compassion. However, if the Government is serious about inclusion, it must honour its responsibility to reimburse expenses to the private schools on time.

I truly believe education must focus not just on acquiring degrees but being responsible citizens of the world. Our children need a schooling infused with stories of good, hundreds of role models from Gandhi*ji* to an unknown person doing active good. Our children need to be valued not just by the test scores but, as Martin Luther King said, by the content of their character. ...*(Time-bell rings)*... I am convinced this is where each of us can contribute. The nation looks at us, Parliamentarians, and the way we conduct

[Ms. Anu Aga]

ourselves. Can we listen to each other even when we disagree? Can we have healthy debates instead of just making political statements or disrupting the proceedings? Since we are on the subject, let me also submit that I am disappointed that I had to wait for two years for my maiden speech! Frequent turmoils and adjournments did not give me a chance. About 320 million children in this country deserve an excellent education. It is a daunting challenge. More than any other time in our society, we have the resources, ideas and skills to solve a problem of this magnitude. The question is: do we have the will? Are we willing to join hands and work together irrespective of our social background? More importantly, are we bold enough to dream beyond the realities of today? Are we bold enough to dream of the India we all wished to be? ...*(Time-bell rings)*... Let us prove that that we are capable of such dreams and have the will and fortitude to realize them. I invite each of my friends here to make this dream a reality. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Ms. Anu. Now, in the morning, there was a demand from some sections of the House that the hon. Railway Minister should make a statement on the accident occurred today. I hope you agree for that.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, please.

STATEMENTS BY MINISTERS – *Contd.*

Incident occurred at unmanned level crossing on South Central Railway

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Mr. Deputy Chairman, Sir, Members of this House have shown their deep concern over the unfortunate incident occurred today at an unmanned level crossing in South Central Railway. With the permission of the Chair, I am making this Statement before this House.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I am pained to apprise the House regarding an unfortunate incident which has occurred today at an unmanned level crossing wherein one school bus belonging to Kakatiya Techno School carrying children dashed against the train engine of train no.57564 Nanded-Hyderabad Passenger at about 09.15 hrs. on 24.07.2014 between Wadiaram and Maisaipet railway stations on Nizamabad-Secunderabad section of Hyderabad Division of South Central Railway. In this incident, 18 school children including the bus driver lost their lives. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: But, here, it is written 12.